

हरियाणा विधान सभा

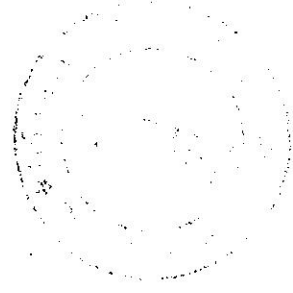
की

कार्यवाही

11 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 11 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	(5) 24
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनराारम्भ)	(5) 24
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 26
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 31
शोक प्रस्ताव	(5) 42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	(5) 43
पंजाब क्षेत्र में एस0वाई0एल0 कैनाल को पूरा करने संबंधी	(5) 43
वक्तव्य-	(5) 44
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी - मुख्यमंत्री द्वारा	(5) 51
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	(5) 51
चौधरी बंसी लाल, द्वारा	(5) 51
व्यक्तव्य उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनराारम्भ)	(5) 51
वाकआउट्स	(5) 57
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(5) 60
वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(5) 71
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(5) 71
अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(5) 71

मूल्य :

68 00

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 11 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारंकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर, अब सवाल होंगे।

तारंकित प्रश्न संख्या 1004

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती सरिता नारायण सदन में उपस्थित नहीं थीं)

Setting up of Fire Station, Kosli

*949. Smt. Anita Yadav : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Fire Station at Sub-Tehsil, Kosli, District Rewari ?

भार विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) : जी, नहीं।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, कोसली सब डिवीजन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से और इज्जर डिस्ट्रिक्ट से 40-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर कोसली शहर में आग लग जाती है तो जब तक इन शहरों से फायर ब्रिगेड पहुंचता है तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि क्या वे कोसली में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने के लिए कोई प्रावधान करेंगे अगर करेंगे तो वह कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, कोसली शहर में न तो नगरपालिका है न नगर परिषद है इसलिए नगरपालिका और नगरपरिषद न होने के कारण वहां पर फायर ब्रिगेड खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है। रेवाड़ी शहर कोसली के नजदीक पड़ता है और रेवाड़ी में पहले ही फायर ब्रिगेड स्टेशन मौजूद है।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, रेवाड़ी शहर कोसली से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और जो कोसली से रेवाड़ी की सड़क है वह काफी टूटी हुई है जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफी देर लग जाती है। अब पिछले दिनों निशाण गांव में कड़वी में आग लग

[श्रीमती अनिता यादव]

गई थी और जब तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तब तक वह सारी कड़की जल कर राख हो गई थी। इसी तरह कोसली में एक दुकान में आग लग गई थी और जब तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तब तक वह सारी दुकान जल कर राख हो गई थी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कोसली शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने का प्रावधान किया जाये। इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या जिन शहरों की नगरपालिकायें भंग कर दी गई थीं वहां के फायर ब्रिगेड स्टेशन हटाने का सरकार का विचार है, अगर नहीं तो फिर हमारे यहां कोसली में फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है।

श्री सुभाष गोयल : स्पीकर महोदय, जिन नगरपालिकाओं की आबादी 15 हजार या 15 हजार से ज्यादा है वहां नगर पालिका एग्जिस्ट हो सकती है। ऐसी किसी नगर पालिका को भंग नहीं किया गया है और जिन नगरपालिकाओं को भंग किया गया है और जहां पर फायर ब्रिगेड स्टेशन की सुविधा नहीं थी वहां पर वह सुविधा देने का कोई प्रावधान करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब आ गया है।

Opening of Mini Bank

*1010. Sh Rambir Singh : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open Mini Bank in Badhra Constituency ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : नहीं, श्रीमान् जी, बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में पहले ही 35 मिनी बैंक कार्यरत हैं।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि बाढ़ड़ा क्षेत्र में 35 मिनी बैंक हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 107 गांव हैं और इन में दो बड़े गांव काकड़ौली और पिचोपा कला हैं वहां पर मिनी बैंक नहीं हैं। क्या मंत्री जी इन बड़े गांवों में मिनी बैंक खोलने का कष्ट करेंगे या भविष्य में सरकार की कोई ऐसी नीति है कि इन गांवों में मिनी बैंक खोलने पर विचार किया जा सके।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में पहले ही 35 मिनी बैंक कार्यरत हैं और वहां के निवासियों की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई मांग हमारे पास नहीं आई है अगर ऐसी कोई मांग आई तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के दो बड़े गांव काकड़ौली और पिचोपा कला की पंचायतों ने इस बारे में लिख कर एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा हुआ है इस बारे में मैंने भी अपना सुझाव रखा था तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वे इन गांवों में मिनी बैंक खोलने पर विचार करेंगे।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मिनी बैंक खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या कंडीशंस हैं कृपा करके बतायें।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जिस गांव में 60 लाख रुपये तक कर्जा लेने वालों की संख्या हो वहां मिनी बैंक खोला जा सकता है।

श्री जसवीर सिंह मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में भी मिनी बैंकों की कमी है। पिछले दिनों आई0सी0डी0पी0 स्कीम के तहत जनमुई हैड पर एक्सटेंशन काउंटर खोला गया था लेकिन अभी तक उसको ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया है जिसकी वजह से 40 गांव प्रभावित हैं और उनको दूसरी शाखाओं में लेन देन के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री महोदय भी पिछले दिनों माजरी गांव में गए थे वहां उनके सामने इस बारे में मांग पत्र रखा गया था और उन्होंने वहां आश्वासन दिया था कि इस एक्सटेंशन काउंटर को ब्रांच का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन अभी तक उसको ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसको ब्रांच का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ?

श्री करतार सिंह भड़ाना : अभी इस पर विचार चल रहा है।

श्री शशि रंजन परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के मुंढाल में मालकोस मिनी बैंक खुला हुआ है लेकिन वह बैंक मालकोस की बजाय नीमड़ी में है। इससे दो तीन गांवों में डिस्प्यूट है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि यह बैंक जिस गांव के नाम से खोला गया है उसी गांव में खोला जाएगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह बैंक उसी गांव में होना चाहिए जिस गांव के नाम से खुला हुआ है या फिर उसका ब्रांचरकेशन कर दिया जाए इसके लिए केस आर0सी0एस0 आफिस में आया हुआ है और अगर ऐसा हो जाता है तो वहां के 2-3 गांवों का डिस्प्यूट सैटल हो जाएगा।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अगर नार्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री रामकुमार नथूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि उचाना कला में मुख्यमंत्री महोदय ने मिनी बैंक खोलने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक वह मिनी बैंक खोला नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उसमें कौन सी कार्यवाही बाकी रह गई है जिसकी वजह से यह मिनी बैंक खोला नहीं गया है।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि वे ये सवाल अलग से दें। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दे दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह बादय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मिनी बैंक सोसायटीज हैं क्या इनसे 50 रुपये से ज्यादा लोन लेने वाले किसानों के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगाई हुई है ?

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सीनियर साथी को बताना चाहता हूँ कि वे इस बारे में अलग से नोटिस दे दें।

तारांकित प्रश्न संख्या-1008

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भीम सैन मेहता सदन में उपस्थित नहीं थे।

Strengthening of Power Distribution system

*966 Sh. Ramesh Rana : Will the Chief Minister be pleased to state :

- whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the Power Distribution System in Karnal Circle; and
- whether there is any proposal under consideration of the Govt., to set up new 33KV Sub-Stations/augmentation 33 K.V. sub-station in Karnal Circle; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

(क) हाँ श्रीमान, करनाल परिमण्डल में पावर वितरण प्रणाली को 54 अत्याधिक ओवर लोडिड 11 के0वी0 फीडरों का पुन-स्थापना तथा द्वि-भाजन करके तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों को जोड़कर नए उपकेन्द्रों का निर्माण तथा चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करके सुदृढ़ किया जा रहा है। एक नया 33 के0वी0 उपकेन्द्र चालू किया गया है तथा 11 नं0 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता पहले ही बढ़ाई जा चुकी है।

(ख) हाँ श्रीमान, 17.30 करोड़ रुपये की लागत से सम्बन्धित लाईनों के साथ 11 नए 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 12 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव है।

इन कार्यों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ए) करनाल सर्कल में निर्माण किए जा रहे 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम	प्रस्तावित क्षमता (एमवीए में)	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6
1.	पाङ्डा	करनाल	करनाल	6.3	2002-03
2.	मंजुरा	करनाल	करनाल	6.3	2002-03
3.	जीटीरोड़, पानीपत	करनाल	पानीपत	6.3	2002-03
4.	कुटानी रोड़, पानीपत	करनाल	पानीपत (2X6.3)	12.6	2002-03
5.	सिवाह/दीवाना	करनाल	पानीपत	6.3	2002-03
6.	असंध रोड़, पानीपत	करनाल	पानीपत (2X6.3)	12.6	2003-04
7.	बापोली	करनाल	पानीपत	6.3	2003-04
8.	डाहर	करनाल	पानीपत	6.3	2003-04
9.	निगधू	करनाल	करनाल	6.3	2002-03
10.	थल	करनाल	करनाल	6.3	2003-04
11.	सलवान	करनाल	करनाल	6.3	2003-04

(बी) करनाल सर्कल में निर्माण किए जा रहे 33 के0वी0 लाईनों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	33 के0वी0 लाईन का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम (एमवीए में)	प्रस्तावित क्षमता	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6
1.	132के0वी0 उपकेन्द्र जुडला-पाङ्डा लाईन	करनाल	करनाल	16	2002-03
2.	132 के0वी0 उपकेन्द्र जुडला-मंजुरा लाईन	करनाल	करनाल	7	2002-03

[श्री रामपाल माजरा]

1	2	3	4	5	6
3.	132के0वी0 उपकेन्द्र चंदौली-जीटी रोड पानीपत लाईन	करनाल	पानीपत	6	2002-03
4.	टीऑफ चंदौली-- सुनौली रोड पानीपत लाईन 33 के0वी0 उपकेन्द्र कुटनी रोड, पानीपत के लिए	करनाल	पानीपत	0.2	2002-03
5.	400 के0वी0 उपकेन्द्र सिवाह 33 के0वी0 उपकेन्द्र, सिवाह दीवाना लाईन	करनाल	पानीपत	4	2002-03
6.	टी-ऑफ रोहाना रोड पानीपत-मुनक लाईन असंध रोड, पानीपत के लिए	करनाल	पानीपत	0.5	2003-04
7.	132के0वी0 उपकेन्द्र छाजपुर-बापोली लाईन	करनाल	पानीपत	10	2003-04
8.	132 के0वी0 उपकेन्द्र मतलौड़ा प्रस्तावित- डाइर लाईन	करनाल	पानीपत	12	2003-04
9.	132के0वी0 उपकेन्द्र सग्गा-निगधू लाईन	करनाल	करनाल	13	2003-04
10.	132के0वी0 उपकेन्द्र असंध-थल लाईन	करनाल	करनाल	12	2003-04
11.	132के0वी0 उपकेन्द्र असंध-सलवान लाईन	करनाल	करनाल	11	2003-04
योग				81.7	

(सी) जिला करनाल में 33के0बी0 वर्तमान उपकेन्द्रों की वृद्धि किए जा रहे उपकेन्द्रों का विवरण :-

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम	क्षमता (एमवीए)		अतिरिक्त क्षमता (एमवीए)	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6		
				से	तक		
1.	बलाह	करनाल	करनाल	2X5	2X6.3	2.8	2002-03
2.	कोहांड	करनाल	करनाल	5+4	2X6.3	3.6	2002-03
3.	उपलाना	करनाल	करनाल	5+6.3/8	6.3+	1.3	2002-03
					6.3/8		
4.	काछवा	करनाल	करनाल	1X5	2X5	5	2002-03
5.	धर्मगढ़	करनाल	करनाल	5+4	2X5	1	2002-03
6.	तारावड़ी	करनाल	करनाल	5+6.3/8	6.3+	1.3	2002-03
					6.3/8		
7.	कुटैल	करनाल	करनाल	5+4	2X6.3	3.6	2002-03
8.	मेरठ रोड	करनाल	करनाल	5+6.3/8	6.3+	1.3	2003-04
					6.3/8		
9.	आचर	करनाल	करनाल	2X5	2X5.5	2.6	2003-04
10.	नगला मेधा	करनाल	करनाल	4+5	2X6.3+5	2.3	2003-04
				+6.3			
11.	घीड़	करनाल	करनाल	2X5	2X6.3	2.6	2003-04
12.	बरसत	करनाल	पानीपत	5+6.3/8	6.3+	1.3	2003-04
					6.3/8		
कुल-अतिरिक्त क्षमता (एमवीए)						28.5	

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह जो कार्य शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं वे कब तक पूरे हो जाएंगे ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इन कार्यों के पूरा होने का जो प्रोग्राम है उनके बारे में जवाब इस पटल पर रखी सूची में दिया गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यह सूची पढ़ देता हूँ लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि यह बहुत लम्बी-चौड़ी सूची है। अध्यक्ष महोदय, वैसे इस सूची में लिखा हुआ है कि ये कार्य 2002-2003 और 2003-2004 तक पूरे हो जाएंगे। अगर सारा सदन जानना चाहेंगा कि हमारी सरकार ने बिजली के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कितनी ज्यादा बिजली पैदा की और उसका वितरण बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं जिसकी वजह से हरियाणा के किसानों का कृषि का उत्पादन बढ़ा और प्रदेश का नाम रोशन हुआ तथा हमारे किसानों ने सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा अन्न देने का काम किया। स्पीकर सर, यदि आप कहेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं हाउस में पढ़कर सुना देता हूँ लेकिन इसमें काफी समय लग जायेगा।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० साहब से पूछना चाहूंगा कि जो सवाल मेरे साथी रमेश राणा ने पूछा है मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि जिला करनाल के अंदर 11 के०वी० और 33 के०वी० के कितने ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है और करनाल सर्कल के अंदर कहां-कहां पर 11 के०वी० और 33के०वी० के सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जायेगी।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी कृष्णपाल जी को इस महकमें की बहुत नॉलेज है इसलिए इनकी संतुष्टि के लिए और पूरे सदन की संतुष्टि के लिए बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 35 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है और चौधरी भजन लाल जी फिर कहेंगे कि मैंने इतना ज्यादा बता दिया क्योंकि काम ही इतना हुआ है जिसको बताने में समय तो लगेगा ही इसलिए मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि करनाल जिले में भादसों, एन०डी०आर०आई०, क्रिमिच, मेरठ रोड़ करनाल, तरावड़ी, ईसराना, जाम्बा, सनोली रोड़ पानीपत, टोहाना की एच०एस०आई०डी०सी०, उकलाना, डिकाडला, अजराना, खानपुर, कोलियां, गोदणी, मखाना, ज्योतिसर, लूखी, चहु-लदाणा, चिक्का, खेड़ी गुलाम वाली, भिसाद, बाढ़ला, मस्तगढ़, एच०एस० आई०डी०सी० पुण्डरी, खरखौदा, छाजपुर, अटेरना, लघु सचिवालय सोनीपत, फरमाना, बादली, झंजर, बपूनिया, अलेवा, बूढकलां, बाराखास रोड़ अम्बाला आदि सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से पूछना चाहूंगा कि सड़ौरा के अंदर ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज्यादा है, वहां पर 16 एम०वी०ए० का एक ही ट्रांसफार्मर है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने वहां के लिए 16 एम०वी०ए० का एक और ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा की थी वह कब तक लग जायेगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने एक स्पैसिफिक प्रश्न पूछा है इसको हमने नोट कर लिया है इसको एग्जामिन करवा लेंगे यदि नार्मल पूरे करता होगा और वास्तव में ही वहां लोड ज्यादा होगा तो एग्जामिन करवाने के बाद इसे टेकअप कर लिया जायेगा। स्पीकर सर, हमारा तो काम ही लोड कम करने का है हम चाहते हैं कि किसान की और हमारे कन्ज्यूमर को अधिक से अधिक सुविधा हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 17.30 करोड़ रुपये स्ट्रैथनिंग ऑफ दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर खर्च किए जा रहे हैं।

इतना पैसा खर्च करने के बाद लाईन लोसिज कितने प्रतिशत कम होंगे और अब लाईन लोसिज कितने प्रतिशत हैं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सब-स्टेशनों की क्षमता इसलिए बढ़ाई जाती है कि फ्रिक्वेंसी तेज हो, लोसिज कम हों। कैप्टन साहब जो जानना चाहते हैं ये उसका अलग से नोटिस दे दें हम उस बारे में इनको बता देंगे। स्पीकर सर, पूरे हरियाणा प्रदेश में सब स्टेशन लगाये जायेंगे, अपग्रेड किए जायेंगे, लाईनों को बाइफ्रेजेंट करेंगे और उनका लोड कम करके लाईन लोसिज भी कम करेंगे। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भाजरा साहब ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न लाईन लोसिज से संबंधित नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैटिये-बैटिये।

Strengthening of Distribution of Power

*917. Sh. Banta Ram Balamiki : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the distribution system of Power in various Circle in the State, if so, the details thereof from the year 1999 to date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : हैं श्रीमान, राज्य के विभिन्न परिमण्डलों में विद्युत वितरण प्रणाली को 11 के0वी0 भारी रूप से ओवर लोडेड बोझिल फीडर्स को दो भागों/तीन भागों में बांट कर तथा पुनः सक्षम करके, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जोड़कर तथा 33 के0वी0 नये उपकेन्द्रों का निर्माण करके एवं 33 के0वी0 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करके सुदृढ़ किया जा रहा है। 12 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा उनसे सम्बन्धित 211 किलो मिटर 33 के0वी0 लाइनें चालू की गई हैं तथा जुलाई 1999 से राज्य में 57 चालू 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

इन कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दर्शाते वाला एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

राज्य में वितरण विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जुलाई, 1999 से निम्न कार्य क्रियान्वित किए गए हैं -

1. 33 के0वी0 कार्य

(ए) नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	जिले का नाम	क्षमता (एमवीए में)	चालू होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	देवशाला	भिवानी	1X6.3	30-7-1999
2.	चीका	कैथल	1X4	31-7-1999

[श्री रामपाल भाजरा]

1	2	3	4	5
3.	सिंधाना	जींद	1X4	5-1-2000
4.	जहाजगढ़	झज्जर	1X6.3	19-1-2001
5.	कवालरन	कैथल	1X4	23-3-2001
6.	आई0ए0सिरसा	सिरसा	1X4	27-5-2001
7.	सूर्या रोशनी	झज्जर	1X6.3	28-6-2001
8.	बियाना	करनाल	1X6.3	30-7-2001
9.	गेन्दा	फतेहाबाद	1X4	31-8-2001
10.	खुशपुरा	रिवाड़ी	1X5	30-9-2001
11.	बावनिया	नारनौल	1X6.3	8-2-2002
12.	डबलाना	नारनौल	1X6.3	10-2-2002

बी0वी0 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि

क्र0 सं0	उपकेन्द्र का नाम	जिले का नाम	क्षमता (एम0वी0ए0 में)	जोड़ी गई क्षमता (एम0वी0ए0 में)	पूर्ण होने की तिथि	
1	2	3	4	5	6	
			से	तक		
1.	भाइस्तों	करनाल	2X5	2X5+4	4	15-7-1999
2.	एन0डी0आर0आई रामनगर करनाल	करनाल	6.3/8 4	2X6.3/8	4	18-7-1999
3.	किरमीच	करनाल	5+4	5+6.3/8	4	18-5-2000
4.	मेरठ रोड़ करनाल	करनाल	2X5	5+6.3/8	3	20-5-2000
5.	तरावड़ी	करनाल	2X5	5+6.3/8	3	15-7-2000
6.	इसराना	पानीपत	2X5	3X5	5	15-7-1999
7.	जाम्बा	करनाल	5+6.3	6.3+ 6.3/8	3	19-8-2000
8.	सनौली रोड़ पानीपत	पानीपत	5+6.3	2X6.3+5	6.3	1-11-2000
9.	कोहान्ड	पानीपत	1X4	4+5	5	7-11-2000
10.	उपलाना	पानीपत	1X6.3/8	6.3/8+4	4	24-1-2001
11.	डिकाडला	पानीपत	2X6.3	2X6.3+5	5	27-3-2001
12.	अजराना	कुरुक्षेत्र	2X6.3	2X6.3+4	4	15-7-1999

1	2	3	4	5	6	
13.	खानपुर कोलियाँ	कुरुक्षेत्र	2X6.3	2X6.3+4	5	15-7-1999
14.	बोधनी	कुरुक्षेत्र	2X4	4+6.3	2.3	30-7-1999
			4+6.3	2X6.3	2.3	6-10-2001
15.	मथाना	कुरुक्षेत्र	4+6.3/8	2X6.3/8	4	7-1-2000
16.	ज्योतिसर	कुरुक्षेत्र	3+4	2X4+6.3/8	4	15-5-2000
17.	लूखी	कुरुक्षेत्र	4+6.3	2X6.3	2.3	9-1-2001
18.	चाकुलदाना	कैथल	3X5	2X5+6.3	1.3	28-7-1999
19.	चौका	कैथल	2X4	5+4	1	17-8-1999
20.	खेड़ी गुलाम अली	कैथल	2X4	4+6.3/8	4	7-3-2000
21.	इशाक	कैथल	2X4	4+6.3/8	4	30-3-2000
			4+6.3/8	6.3+6.3/8	2.3	20-7-2001
22.	पाडला	कैथल	2X4+6.3	2X6.3+4	2.3	10-1-2001
23.	मरस्तगढ़	कैथल	4+6.3	2X6.3	2.3	7-8-2000
24.	एच0एस0आई0डी0सी0 कुण्डली	सोनीपत	6.3+6.3/8	2X6.3/8	1.7	16-7-1999
25.	खरखोदा	सोनीपत	6.3+6.3/8	2X6.3/8	1.7	21-7-1999
26.	ताजपुर	सोनीपत	5+6.3/8	2X6.3/8	3	14-8-1999
27.	अटेरना	सोनीपत	1X4	2X4	4	26-11-1999
28.	लघु सचिवालय सोनीपत	सोनीपत	5+6.3/8	2X6.3/8	3	15-1-2000
29.	फरमाना	सोनीपत	1X4	1X5	1	30-11-2000
30.	बादली	झज्जर	1X5	1X6.3/8	3	3-11-1999
31.	झज्जर	झज्जर	2+4	6.3+4	4.3	17-7-2001
32.	भूपनियां	झज्जर	1X4	1X6.3	2.3	3-8-2001
33.	अलेवा	जींद	1X4	6.3/8	4	3-11-1999
			1X6.3/8	1X6.3/8+4	4	8-8-2001
34.	बुधकलां	यमुनानगर	1X4	2X4	4	16-1-2001
35.	12 क्रॉस रोड अम्बाला छावनी	अम्बाला	2X6.3	3X6.3	6.3	4-6-2001
36.	मुन्डिया खेड़ा	नारनौल	2X6.3	6.3+6.3/8	1.7	9-7-1999
			6.3+6.3/8	6.3+6.3/8	1.7	18-7-1999
37.	भाड़ावास	नारनौल	1X4	1X6.3	2.3	22-11-2001

[श्री रामपाल माजरा]

1	2	3	4	5	6	
38.	पहलवास	नारनौल	1X2	1X4	2	26-11-2001
39.	कान्ती	नारनौल	1X2	1X5	3	30-1-2001
40.	थेडबलपुर	हिसार	1X4	1X6.3	2.3	15-7-1999
41.	विद्युत नगर हिसार	हिसार	1X5	1X6.3/8	3	29-5-2000
42.	एच0टी0एम0 हिसार	हिसार	1X4	1X6.3	2.3	24-2-2001
43.	अग्रौडा	हिसार	1X4	1X6.3	2.3	1-6-2001
44.	भट्टू	फतेहाबाद	1X2	1X4	2	23-7-2001
45.	रैनवाली	सिरसा	1X4	1X6.3	2.3	20-7-1999
46.	कालावाली	सिरसा	1X4	1X5	1	26-7-1999
47.	गंगा	सिरसा	1X2	1X4	2	27-8-1999
			1X2	1X4	2	9-11-2001
48.	पन्जुआभा	सिरसा	1X4	1X6.3	2.3	14-10-1999
			1X5	1X6.3	1.3	16-6-2001
49.	बहुदीन	सिरसा	1X5	1X6.3/8	3	10-8-2001
50.	कालावाली	सिरसा	1X4	1X6.3	2.3	18-10-2000
51.	कादमा	भिवानी	1X2	1X5	3	15-10-1999
52.	लोहारू	भिवानी	1X4	1X6.3	2.3	28-10-1999
53.	इशरथाल	भिवानी		1X6.3	6.3	8-1-2001
				(अतिरिक्त)		
54.	सिवानी	भिवानी		1X4	4	12-8-2000
				(अतिरिक्त)		
55.	आई0ए0भिवानी	भिवानी		1X4	4	6-1-2001
				(अतिरिक्त)		
56.	लोहारू	भिवानी	1X5	1X6.3	1.3	27-4-2001
57.	एस्कोटर्स	फरीदाबाद	1X2	1X6.3	4.3	30-11-1999
	योग:				193.7	

(सी) 33 के0वी0 लाइनें

राज्य में जुलाई 1999 से 211 कि० 33 के०वी० लाइन का निर्माण तथा चालू की गई है।

2. 11 के०वी० कार्य

विभाजन/त्रिभाजन के बाद 80 नं० भारी बोझिल 11 के०वी० फीडर 157 नं० फीडर में तबदील कर दिए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में जुलाई 1999 से निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए गए हैं-

क्र०सं०	विवरण	यूनिट	मात्रा
1	2	3	4
1.	11 के० वी० लाइनों का निर्माण	कि०मी०	2005 यू०एच०बि०वि०एन०-1010, डी०एच०बि०वि०एन०-995
2.	एल०टी०लाइनों का निर्माण	कि०मी०	1651 /यू० एच०बि०वि०एन०-675/ डी०एच०बि०वि०एन०-996/
3.	जोड़े गए वितरण ट्रान्सफार्मर न०		12204 /यू०एच०बि०वि०एन०-6145, डी०एच०बि०वि०एन०-6059/

इन कार्यों के क्रियान्वयन के साथ ही विद्युत प्रणाली में बाधाएँ/ब्रेक डाऊन घट गए हैं तथा प्रणाली की विश्वसनीयता और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी काफी हद तक सुधार हुआ है।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : स्पीकर साहब, मैं इस समाज के दधालु मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2002-2003 में 33 के०वी० के कितने सब स्टेशन लगाये जा रहे हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं माननीय साधु श्री बन्ता राम जी को यह बताना चाहूँगा कि 2002-2003 के अन्दर 33 केवी के कितने नये उप केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। सर, 21 उप केन्द्र तो उत्तरी विद्युत प्रसारण निगम तथा 11 उप केन्द्र दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम बनायेगा। ये जो उप केन्द्र बनाये जायेंगे इनके नाम इस प्रकार हैं- पाढा, करनाल में, मन्जुश करनाल में, जी०टी० रोड करनाल में, उटानी रोड पानीपत में, सिवाह पानीपत में, झाँयसा कुरुक्षेत्र में, नैसी कुरुक्षेत्र में, मुखली कुरुक्षेत्र में, जाखोली कैथल में, वर्योडक कैथल में, खेवड़ा सोनीपत में, केहरवाला सिरसा में, मंगाली हिसार में, रसूलपुर खेड़ी सिरसा में, खारिया सिरसा में, मेलाग्राम सिरसा में, उमड़ा हिसार में, सदनवास हिसार में, दरियापुर हिसार में, नारनौद हिसार में इसके अतिरिक्त करनाल जिले के गाँव राहड़ा में भी 33 के०वी० का उप केन्द्र स्थापित करने का कार्य विचाराधीन है। स्पीकर साहब, इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा भी 11 उप केन्द्र बनाये जायेंगे।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें लाडवा, धबान और रादौर का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहां पर पैडी सीजन में बिजली की बड़ी भारी दिक्कत आती है। स्पीकर साहब, पड़ोस में शादी हो तो उसका हमें क्या फायदा। अर्थात् मैं

[श्री बन्ता राम बाल्मीकि]

आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लाडवा, रादौर और बाबैन में बिजली की बड़ी भारी दिक्कत है। हमारा एरिया प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्न देता है। हमारा एरिया गेहूँ, जीरी और गन्ने की फसल भी दूसरे प्रदेशों से अधिक पैदा करता है। मंत्री जी ने भिवानी में या दूसरी जगहों पर नये उप-केंद्र बनाने की बात बतायी है। इस बारे में मेरा कहना है कि उन एरियाज में तो जीरी की फसल देखने को भी नहीं होती। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बाबैन, रादौर और लाडवा के अन्दर भी नये सब-स्टेशन बनाने की तरफ ध्यान रखा जाये ताकि हम वहाँ पर धरती माता का सीना चीर कर और अधिक अन्न पैदा कर के समाज का भरण पोषण कर सकें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, कहीं पर भी सब-स्टेशन बनाये जाने के लिए बाकायदा कुछ टर्म्ज एण्ड कन्डीशंस होती हैं। मैं इनकी जाणकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पहले प्लान में इनका काफी ख्याल रखा गया था। बन्ता राम जी की यह बात सही है कि वहाँ पर और जगहों की अपेक्षा डिमांड भी ज्यादा है और वहाँ का एरिया भी फर्टाइल है और वहाँ के किसान भी मेहनती हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि वे वहाँ पर फिर भी किसी विशेष जगह पर ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो वे उसके लिए लिख कर भेज दें, उसको एग्जामिन करवा लेंगे और वह स्थान नार्मल पुरे करता होगा तो बन्ता राम जी की बात को पूरा अधिमान दिया जायेगा।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हम कई साल से सुन रहे हैं कि हम दो साल में इतनी बिजली पैदा करेंगे कि हमें बेचनी पड़ेगी। (विद्य)

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, आप स्पीच न दें, केवल सप्लीमेन्टरी पूछें।

श्री धर्मवीर सिंह : सर, मैं सप्लीमेन्टरी ही पूछ रहा हूँ। स्पीकर साहब, बड़े दुःख की बात है कि भिवानी जिले में बिजली की दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है। (विद्य) स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आज के दिन सतनाली से लेकर लोहारू, बहल, नक्कीपुर, तोशाम और जमालपुर के इलाके में कोई 33 के0वी0 का या 132 के0वी0 का नया सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो वह कब तक चालू करेंगे। अब तक तो इनके दो साल निकल गये और यदि काम न किया तो फिर आगे के भी 2-3 साल ऐसे ही निकल जायेंगे। (विद्य)

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी जगह चाहते हैं, वह जगह आप बताएं। आपने तो 6-7 जगह बता दी, आप कोई पार्टिकुलर जगह बताएं जहाँ पर आप सब-स्टेशन बनवाना चाहते हैं। (विद्य)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे थक जानना चाहता हूँ कि ये किस जगह पर सब-स्टेशन चाहते हैं, यह तो बताएं।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम ऑलरैडी बताए हैं ये नाम हैं नक्कीपुर, तोशाम, सतनाली, बहल, लोहारू, जमालपुर।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 100 किलोमीटर लम्बे एरिया का इकट्ठा मांग लिया और 100 किलोमीटर लम्बी लाइन की गिनती कर दी। मैं इनको बताना चाहूँगा कि जहाँ

पर इनका इन्ट्रस्ट है ये यहाँ की बताएं। वास्तव में इन्हें जहाँ किसान मिलते हैं और लोगों ने मांग की हो कि हमें सब-स्टेशन चाहिए, ये बताएं। अपनी मांगों को लेकर लोग इनके पास आए हों और कहा हो कि हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं आप इस पर विचार करें। अगर लोग इनसे मिले हों या कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह इनको दी हो तो उस पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन अगर यह सारी सौ किलोमीटर सड़क का कहें तो प्रॉब्लम है कोई स्पैसिफिक सब-स्टेशन ये चाहते हैं तो बता दें हम उसे एग्जामिन करवा लेंगे। अगर वह नॉर्मल, टर्मज एण्ड कण्डीशनज को पूरा करता होगा तो इस पर जरूर गौर करेंगे।

डॉ० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरे इल्के में जहाजगढ़ का सब-स्टेशन है क्या यह पूरी कैपेसिटी पर चल रहा है और अगर यह पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है तो क्या ये इसको एग्जामिन करवाएंगे कि यह कैपेसिटी पर चले, अगर हां तो यह कब तक पूरी कैपेसिटी पर चल पाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न क्लीयर नहीं हुआ है इन्हें अपना प्रश्न क्लीयर करने के लिए कहने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : आप सब-स्टेशन का नाम तो बताएं ?

डॉ० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जहाजगढ़ का सब-स्टेशन 166 के०वी०ए० की प्रपोज्ड कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है, यह कब तक अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल पाएगा ? (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी यह बताएं कि क्या जहाजगढ़ का सब-स्टेशन वास्तव में ओवर लोडिड है ?

डॉ० रघुवीर सिंह कादयान : यह पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहाजगढ़ का सब-स्टेशन वास्तव में ओवर लोडिड है, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे अगर बाईफरकेट या ट्राईफरकेट लाईमें जाएगी तो वह बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। इसके बारे में पूरा विवरण सदन के पटल पर जानकारी के लिए रखा है, यह इसमें देख लें।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि 11 के०वी०ए०, 132 के०वी०ए० या 33 के०वी०ए० के सब-स्टेशन के अतिरिक्त वर्ष 2002-03 में नये पावर हाउस लगाने विचाराधीन हैं और भेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार आपके द्वार के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे इल्के में 2 दरबार लगाए। सालवन गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है वहां पर 33 के०वी०ए० के पावर हाउस की लोगों की डिमाण्ड थी और मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए YES भी किया है। मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने जो लिस्ट सदन के पटल पर रखी है उस लिस्ट में इस का नाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस गांव को इस लिस्ट में शामिल करने बारे विचार करेंगे ?

श्री रामपाल माजरा : जितने भी ओवर लोडिङ सब-स्टेशनज़ होते हैं उनका प्रोग्राम या नामों की डिमाकेशन पहले नहीं होती है, सबसे पहले उनकी जांच की जाती है और उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगले वर्ष के लिए 38 सब-स्टेशनज़ की जो सूची है उसमें पंवार साहब ने जो नाम बताया है वह गांव शामिल नहीं हैं लेकिन वह लिस्ट चेन्ज भी की जा सकती है, वह बदली भी जा सकती है। कहीं पर भी अगर ओवर लोडिंग हो जाए तो उस पर जांच की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पंवार साहब को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जिस बड़े गांव की चर्चा की है अगर वह नॉर्मज़ पूरे करता होगा तो वर्ष 2002-03 के प्रोग्राम में उसका नाम नहीं है तो भी उसके नाम पर जरूर विचार करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानकारी चाहूंगा। इन्होंने राज्य के विभिन्न सर्कलों में बिजली की वितरण व्यवस्था की मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पटल पर रखा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में ऐस्कोर्ट के अतिरिक्त कोई नाम नहीं है। हथीन विधान सभा क्षेत्र में हथीन और औरंगाबाद के बारे में क्या सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और अगर है तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक क्षमता बढ़ाने का प्रश्न है, 32 सब-स्टेशनज़ की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर मैं इन सबके नाम बताने लग जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। यह एक तरह का प्रोग्राम है इसमें ऐसा नहीं है कि यह कांस्टीच्यूरेंसी-वाईज होगा या हथीन में अलग से होगा। यह क्षमता बढ़ाने के बारे में प्रोग्राम है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस साल में 32 सब-स्टेशनज़ की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 914

(क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भाग सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं थे यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Opening of National Law College at Gurgaon

*862 Sh. Bhagi Ram : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether a National Law College has been opened at Gurgaon; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : हां, श्रीमान् जी। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय खोला गया है। इस महाविद्यालय में अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के अन्तर्गत पाँच वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय में जो दाखिला होता है वह किस क्राइटेरिया के अनुसार होता है और जब इस कालेज में दाखिला होता है तो उसमें अनुसूचित जातियों के बच्चों को ध्यान में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय खोला गया है जिसका उद्घाटन 7 अक्टूबर, 2001 को मुख्य

मंत्री जी द्वारा किया गया था। अर्द्धशासित पाठ्यक्रम प्रणाली के अन्तर्गत 5 वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाने का लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाविद्यालय में दाखिले अखिल भारतीय विद्या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं। अतः 50 फीसदी सीट्स हरियाणा प्रदेश के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित हैं। दाखिले के मामले में हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति के कार्यक्रम का पालन पूर्णतः किया जाता है। हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा भारतीय विधि परिषद् के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महाविद्यालय गुड़गांव सेक्टर-40 में एक सुन्दर मवन में स्थित है। महाविद्यालय का क्षेत्र लगभग 10 एकड़ तक का है। हरियाणा सरकार द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाविद्यालय के लिए भूमि निःशुल्क प्रदान की गयी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आरक्षण दिए जाने की बात है, जो आरक्षण नीति सरकार की है उसी के हिसाब से इस कालेज में भी आरक्षण दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो कालेज गुड़गांव में खोला गया है यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या मंत्री जी मुझे बताएंगे कि इस कालेज के एडमिशन में एन0आर0आईज0 को और पेड सीट्स के लिए कोई प्रावधान रखा गया है, अगर रखा गया है तो कितना पैसा पेड सीट के लिए रखा गया है और कितने प्रतिशत सीट्स इनके लिए हैं। अगर इनके एडमिशन के लिए जो पैसा रखा गया है वह बहुत ज्यादा है तो क्या सरकार इसको कम करने के बारे में विचार करेगी ?

चौधरी बहादुर सिंह : आप इस बारे में कोई स्पैसिफिक केस बता दें। वैसे हमारी सरकार की यह पॉलिसी है कि 50 प्रतिशत सीट्स हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए और 50 प्रतिशत बाहर के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपके पास फीस से रिलेटिड कोई स्पैसिफिक केस है तो आप उस बारे में सैप्रेटली लिखकर दे दें हम इसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में खास करके जो मेवात का इलाका आता है, वहां पर बहुत ही पिछड़ापन है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद या रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे पिछड़े हुए या गांव में रहने वाले हैं क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके दाखिले के लिए कालेज में कोई रियायत देने का प्रावधान किया है।

चौधरी बहादुर सिंह : सरकार की पॉलिसी है कि एस0सीज0, बी0सीज0, एस0टीज0 और हैंडिकैप्ड्स के लिए ही आरक्षण नीति है। उसी के हिसाब से उस कालेज में आरक्षण दिया जा रहा है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि एरियावाइज वहां पर कोई आरक्षण नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि गांवों में रहने वालों के जो बच्चे हैं खासकर मेवात के लोगों के, फरीदाबाद और अहीरवाल के गांवों के लोगों के बच्चे हैं जिनके बारे में मंत्री जी ने कहा कि इनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। मैं मंत्री जी से दोबारा पूछना चाहूंगा कि क्या प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों के बच्चों का उस महाविद्यालय में आरक्षण के आधार पर दाखिला हो सकेगा क्या ये इस बारे में विचार करेंगे या नहीं करेंगे ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें इलाकावाइज कोई आरक्षण की नीति नहीं है। सरकार की जो आरक्षण की नीति चल रही है उसके मुताबिक ही आरक्षण वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा वहां से ऐसी कोई डिमांड भी नहीं आयी है कि उनके बच्चों को वहां पर आरक्षण का लाभ देकर एडमिशन देना है। अध्यक्ष महोदय, केवल गुड़गांव में ही नहीं बल्कि रोहतक में भी

[श्रीधरी बहादुर सिंह]

या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी वे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बारे में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर साहब, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन यह मेरे अपने क्षेत्र का मामला है बल्कि क्षेत्र का ही यह मामला नहीं है अपितु जहाँ यह कॉलेज स्थापित है वह मेरे अपने गाँव की भूमि पर है। अभी मेरे एक मित्र ने उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एन0आर0आईज0 के बारे में चिन्ता की और दूसरे मित्र ने वहाँ के क्षेत्र के गाँवों के बच्चों के बारे में चिन्ता की। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उसने वहाँ के एक पिछड़े हुए गाँव झाड़सा की भूमि पर यह कॉलेज स्थापित किया। मैं अपने इन माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि वे एन0आर0आईज0 की चिन्ता न करें। मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करूँगा कि जिस गाँव के अंदर यह कॉलेज खुला है, वे उस गाँव के आउटस्टीज का इसमें एडमिशन के लिए ध्यान जरूर रखें। वे बताएं कि क्या इसमें एडमिशन के लिए वे उनको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे ?

श्रीधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं डिप्टी स्पीकर साहब से गुजारिश करूँगा कि ये इस बारे में पहले पंचायत का प्रस्ताव भिजवाएं। इसके बाद ही सरकार इस बात को विचाराधीन कर लेगी। अगर हो सका तो वहाँ के बच्चों के लिए उस कॉलेज में रिजर्वेशन रखने की व्यवस्था जरूर की जाएगी।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय के बारे में हमारे विपक्ष के लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। जो आज ये काली टोपी पहन कर हाउस में आये हैं, मंत्री जी बताएं कि इनके लिए भी कोई वहाँ पर रिजर्वेशन है या नहीं (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि इनको काली टोपी तो यमुनानगर के इलैक्शन में वहाँ के लोगों ने ही पहना दी थी इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अब ये क्यों काली टोपी पहनकर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, * * * *

श्री जयप्रकाश : स्पीकर साहब, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। अब अगला सवाल होगा।

Rationalizing Teaching Staff

*878. **Sh. Jasbir Singh Mallour :** Will the Minister of State for Education be pleased to state the details of steps taken or proposed to be taken by the Government to rationalize the Teaching Staff on the basis of enrolment of students in the State; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीधरी बहादुर सिंह) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

शैक्षिक अमले को युक्तिसंगत बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम

उच्चतर शिक्षा

सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु असंख्य कदम उठाए गए हैं। पहले वांछित स्थानों पर संस्वीकृत पदों तथा शिक्षकों की अधिकता थी जिसके कारण ग्रामीण महाविद्यालयों में पर्याप्त अमला नहीं था। भारी कमी वाले अर्द्ध शहरी/ग्रामीण महाविद्यालय अमले की कमी की मार झेल रहे थे जबकि शहरी महाविद्यालयों में अमला आवश्यकता से अधिक था। संस्वीकृत पद महाविद्यालय में छात्र संख्या पर पूर्णतः आधारित नहीं थे। अतः सरकार द्वारा संस्वीकृत पदों तथा प्राध्यापकों की असंतुलित तैनाती ठीक करने के लिए विस्तृत युक्तिकरण आरम्भ किया गया। अब पूर्णतः छात्रों की संख्या के आधार पर अमले की तैनाती की गई है। युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मुख्यतः ग्रामीण महाविद्यालयों में 250 प्राध्यापक स्थानान्तरित किए गए हैं। अमले की कमी को पूरा करने के लिए 269 नए भर्ती किए गए प्राध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने नए भर्ती किए गए प्राध्यापकों को तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण महाविद्यालयों में तैनात करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों से आवश्यक डेटा संग्रहीत किया गया है। वांछित छात्रों तथा तैनात शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना की डेटा एन्ट्री की जा रही है। उसके पश्चात् कार्य नॉर्म तथा छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा

सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पहले ही युक्तिकरण किया जा चुका है तथा इसके परिणामस्वरूप 4626 पद फालतू हो गए हैं। फालतू अध्यापकों को उसी जिले में रिक्तियों के समक्ष समायोजित किया जा रहा है। बाकी फालतू अध्यापकों को प्रतिनिधुक्ति पर अन्य जिलों में समायोजित किया जाएगा।

श्री जसवीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो टीचिंग स्टाफ की रैशनेलाइजेशन की पोलिसी लागू की गयी है उसका क्राईटेरिया क्या है ? कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर लगाने की व्यवस्था की गयी है। मंत्री जी ने रिप्लेई में नये अध्यापकों की भर्ती का भी जिक्र किया है, कि इन अध्यापकों को तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाना जरूरी होगा। स्पीकर साहब, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमने अम्बाला में देखा है कि कई अध्यापक दस दस सालों से एक ही स्कूल में शहरों में हैं और वे लॉग स्टे को तोड़ने से रोकने के लिए निचले स्तर पर मिलकर म्यूचुअल केस बनाकर डिपार्टमेंट को भिजवा देते हैं जबकि कई अध्यापक ऐसे भी हैं जो दस-दस सालों से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही पढ़ा रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी पोलिसी है कि इस तरह के टीचर्स का ट्रांसफर किया जा सके।

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु

[चौधरी बहादुर सिंह]

असंख्य कदम उठाए गए हैं। पहले वांछित स्थानों पर संस्वीकृत पदों तथा शिक्षकों की अधिकता थी जिसके कारण ग्रामीण महाविद्यालयों में पर्याप्त अमला नहीं था। भारी कमी वाले अर्द्धशहरी/ग्रामीण महाविद्यालय अमले की कमी की मार झेल रहे थे जबकि शहरी महाविद्यालयों में अमला आवश्यकता से अधिक था। संस्वीकृत पद महाविद्यालय में छात्र पूर्णतः आधारित नहीं थे। अतः सरकार द्वारा संस्वीकृत पदों तथा प्राध्यापकों की असंतुलित तैनाती ठीक करने के लिए विस्तृत युक्तिकरण आरंभ किया गया। अब छात्रों की संख्या के आधार पर अमले की तैनाती की गई है। युक्तिकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण महाविद्यालयों में 250 प्राध्यापक स्थानांतरित किए गए हैं। अमले की कमी को पूरा करने के लिए 269 नये भर्ती किए गए प्राध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने नए भर्ती किए गए प्राध्यापकों को तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण महाविद्यालयों में तैनात करने का निर्णय लिया है। जो 250 कॉलेज लैक्चरर शहरों में बैठे थे उनको बाहर भेजकर उनकी जगह 269 नये भर्ती किए थे वे सारे के सारे रुरल एरियाज में लगाए गए हैं। अब इन्हें सरकार से 152 पद भरने की अनुमति मिल चुकी है 152 पद हम कमीशन को भेज चुके हैं, 76 पद बकाया हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी ऐडवर्टाइजमेंट के लिए एच0पी0एस0सी0 को भेज दिया जाएगा।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो अध्यापक शहरों में सर्विस करते हैं उनको हाउस रेंट ज्यादा दिया जाता है और जो गांव में करते हैं उनको कम हाउस रेंट दिया जाता है जबकि उनका खर्च ज्यादा होता है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करेगी ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार पॉलिसी बना रही है। जो शिक्षक शहरों में काफी दिन से बैठे हैं उनको देहात में भेजेंगे और जो देहात में शुरू से सर्विस कर रहे हैं उनको ऐडजस्टमेंट करके शहर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत रेशनलाइजेशन किया है यह नहीं है कि एक आदमी जैसे अम्बाला कैंट में बैठा है तो वह वहीं के दूसरे स्कूल में चला गया, इस तरह की कोई नीति नहीं है। जो देहात और शहर के हैं उनको आपस में ऐडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री जसवीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्वेश्चन था उसका मैं उत्तर मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रेशनलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है और कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत है और कितना स्टाफ सरप्लस हो गया है ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे राजकीय प्राथमिक स्कूलों में पहले ही युक्तिकरण किया जा चुका है इसके परिणामस्वरूप 4626 पद फालतू हो गए हैं, फालतू अध्यापकों को उसी जिले में रिक्तियों के समक्ष समायोजित किया जा रहा है। बाकी फालतू अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रो० राम भगत : अध्यक्ष महोदय, बड़े फख्र की बात है कि हरियाणा सरकार ने स्कूल और कॉलेजिज के अंदर स्टाफ की जो जरूरत थी रेशनलाइजेशन के तहत और नयी भर्तियों से स्टाफ रेशनलाइजेशन के तहत पूरा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने स्टाफ के बावजूद जो पूरी सीटें हो चुकी हैं क्या कॉलेज और स्कूलज में जो

क्लास टीचिंग हैं क्या उसकी सैक्टिटी को, उसके महत्व को बहाल किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी स्कूल हैं चाहे वे स्कूल शहरों में हैं या गांवों में हैं, खास तौर से ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल हैं वहां क्लासिज में टीचर नहीं होते। बच्चे पढ़ाई के बगैर बैठे रहते हैं वहां पढ़ाई के बगैर बड़ा ही निराशाजनक वातावरण देखने को मिलता है इसलिए वहां छोटी-छोटी पढ़ाई की दुकानें शुरू हो रही हैं और उनमें ज्यादा बच्चे जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में बराबर हाजिरी गिरती जा रही है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो टीचर सरकारी स्कूलों में 16-20 हजार रुपये तमख्वाह ले रहे हैं, क्या वे समाज के साथ, सरकार के साथ और बच्चों के साथ इंसॉफ कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में हरियाणा सरकार व संबंधित शिक्षा विभाग क्या कोई कदम उठा रहे हैं?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में यह काफी चिंता का मामला है हमारी सरकार जब से बनी है तब से आदरणीय चौटाला साहब के नेतृत्व में पूरी कोशिश है कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रोग्रेस पूरी की जाए। हमारे स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे लेकिन जब से नयी शिक्षा नीति लागू की है तबसे काफी फर्क पड़ा है पड़ती कक्षा से अंग्रेजी शुरू की है तब से भी काफी फर्क पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन स्कूलों में हैडमास्टर नहीं हैं या बच्चे खाली बैठे हैं।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेशनेलाइजेशन का सवाल है इसमें देखने को मिला है कि अधिकारियों के लेवल पर ऐसी गलतियां देखने को मिली हैं या सरकार ने की हैं वहां पर इकीकत में जरूरत के हिसाब से न करके पिक एण्ड चूज के हिसाब से ट्रांसफर किए गए हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जहां एक सबैक्ट के लिए दो तीन टीचर्स हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसा कोई नियम बनाने जा रहे हैं कि कोई टीचर इस बात के लिए परेशान न हो कि उसके साथ कोई ज्यादाती हो रही है। सरकारी स्कूलों से परेशान होकर बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या सरकार इन पर कोई रोक लगा रही है और पिक एण्ड चूज की पोलिसी को खत्म कर रही है? क्योंकि टीचर तो चाहे शहर का हो चाहे गांव का लेकिन इस का नुकसान तो बच्चे ही उठाते हैं।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रेशनेलाइजेशन स्कीम सरकार ने बनाई है उसमें यह प्रावधान रखा है कि जिस स्कूल में सरप्लस अध्यापक होंगे वहां से सीनियर अध्यापक को दूसरी नजदीक की जगह में बदला जायेगा इसमें पिक एण्ड चूज वाली कोई बात नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो उच्चतर, माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए रेशनेलाइजेशन की स्कीम बनाई है उनमें सैवशंड पोस्टें कितनी हैं और उनके अग्रेस्ट अपॉइंट कितने अध्यापक कर रखे हैं और जो अध्यापक गांवों में सर्विस करते हैं उनके लिए कोई रूरल अलाऊंस देने का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है जिससे शहरों में ज्यादा सरप्लस स्टाफ न हो।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो शहरों में फालतू अध्यापक हैं रेशनेलाइजेशन स्कीम के तहत ऐसे फालतू अध्यापकों को गांवों में बदलने का सरकार का विचार है और जो गांवों में फालतू और कई सालों से अध्यापक बैठे हैं उनको नजदीक के शहरों में बदलने का सरकार का विचार है।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि प्राइमरी अध्यापकों के 4626 पद फालतू हो गये हैं। जबकि सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना प्राइमरी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है। उस हिसाब से तो पोस्ट्स और बढ़नी चाहिये थीं क्योंकि अंग्रेजी सब्जेक्ट और ऐड किया गया है जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि अध्यापक फालतू हो गये हैं।

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग से अध्यापक नहीं रखे हैं जो अध्यापक प्राइमरी की क्लासिज़ को पढ़ाते हैं वही इंग्लिश का विषय भी पढ़ायेगे। हमने तो रैशनेलाइज़ेशन स्कीम के तहत जो अध्यापक कई सालों से एक ही स्थान पर बैठे हुये हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की स्कीम बनाई है और उनको दूसरे नज़दीक के स्थानों पर ऐडजस्ट करने जा रहे हैं।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ मेरे विधानसभा क्षेत्र साल्हावास के कोसली सब डिवीजन में कई जगह ऐसी हैं जहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं हैं जबकि कोसली सब डिवीजन में 36 बिरादरी रहती हैं। दूसरी तरफ हम एजुकेशन टेक्नालाजी और कंप्यूटर की बात करते हैं। क्या सरकार का कोसली सब-डिवीजन में प्राइमरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान है अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

चौधरी बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि कोसली गांव 4000 आबादी वाला गांव है और अगर वहां कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल हो तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगी (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थड ठीक है कि इन्होंने प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी बालू करके लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इससे स्कूलों में जो बच्चे कम हुए हैं उनके बारे में ये बताएं तथा जो टीचर्स सरप्लस हो गए हैं उनको ये रिट्रैब करेंगे या उनको घर भेज देंगे इस बारे में भी बताएं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसे तो शिक्षा मंत्री जी ने डिटेल् में जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल रैशनेलाइज़ेशन का है। (शोर एवं व्यवधान) जवाब देने की रिसर्पॉसिबिलिटी अकेले पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर की नहीं बल्कि सरकार की कलेक्टिव रिसर्पॉसिबिलिटी होती है। अकेला पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ही नहीं कोई भी मिनिस्टर जवाब दे सकता है। इनको शिक्षा मंत्री जी ने डिटेल् में पढ़कर सुनाया है और डिटेल् में बताया है जहां तक कॉलेजिज़ में रैशनेलाइज़ेशन की बात है, तो जहां कहीं शहर के कॉलेजिज़ में फालतू लैक्चरर है और कहीं गांव में लैक्चरर नहीं हैं तो उनको वहां भेजा गया है इस प्रकार कॉलेजिज़

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

में रेशनेलाइजेशन किया गया है और इसी तरह सकेडरी स्कूलों में रेशनेलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है और प्राइमरी स्कूलों में रेशनेलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। जहां तक 4626 सरप्लस टीचर्स की बात है तो शिक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब डिप्टेल में दे दिया है कि 4626 सरप्लस टीचर्स स्टेट में नहीं बल्कि स्कूलों के अन्दर सरप्लस हैं। जैसे किसी स्कूल में 6 टीचर्स हैं और वहां रिक्वायरमेंट 5 की है तो वहां एक टीचर सरप्लस हो गया। ये 4626 सरप्लस टीचर्स विभिन्न स्कूलों में हैं इनके बारे में मंत्री जी ने पहले ही कहा है, चाहे तो ये रिकार्ड देख लें कि जो ये सरप्लस टीचर्स हैं इनको उसी जिले में ऐडजस्ट किया जाएगा और अगर उसी जिले में ऐडजस्ट नहीं हो सकेंगे तो इनको दूसरे जिले में ऐडजस्ट किया जाएगा। इसलिए सरप्लस का मतलब कोई छंटनी नहीं है बल्कि जहां टीचर्स की कमी है इनको वहां भेजा जाएगा। इनको तो इस बात के लिए एग्जीशिएट करना चाहिए था। रैस्ट एश्योरड किसी की कोई छंटनी नहीं हो रही है। जहां काम होगा इन सरप्लस टीचर्स को वहीं भेजा जाएगा इनको खाली नहीं बैठने दिया जाएगा ताकि वे बच्चे पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में तो सुविधा के अनुसार कहीं एक टीचर बिठा रखा था और कहीं 10 टीचर्स बिठाए हुए थे। अब सुविधा नहीं चलेगी बल्कि काम के हिसाब से टीचर्स को लगाया जाएगा ताकि लोगों को फायदा मिल सके।

श्री. मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। वित्त मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि ये सरप्लस टीचर्स इस बात से हैं कि कुछ स्कूलों में टीचर्स फालतू बैठे थे और कहीं टीचर्स कम बैठे थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में जरूरत होगी उनको वहां डेपुटेशन पर भेजा जाएगा यह ठीक है। (शोर एवं व्यवधान) इन सरप्लस टीचर्स को डेपुटेशन पर ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आलरेडी आन रिकार्ड आप कह रहे हैं कि 4626 टीचर्स सरप्लस हैं और उनका रेशनेलाइजेशन किया जा रहा है तो पिछले दिनों जो 5000 जे0बी0टी0 टीचर्स की भर्ती की गई है वह किस परपज से की गई है ?

श्री0 सम्मत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कॉलेज से लेकर स्कूल तक की पॉलिसी के बारे में दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे किसी कॉलेज में कॉमर्स लैक्चरर की एक पोस्ट सैक्शन है। और वहां पर स्टूडेंट एक भी नहीं है और किसी दूसरे कॉलेज में 40 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से जिस कॉलेज में स्टूडेंट नहीं हैं वहां पोस्ट सरप्लस हो गई इसलिए जहां स्टूडेंट हैं हम लैक्चरर को वहीं भेजेंगे। इसी तरह से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के बारे में जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी रिप्लाय में बताया है कि Surplus teachers are being adjusted against vacancies in the same District. Remaining surplus teachers shall be adjusted in other districts on deputation. इस तरह से प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ऐडजस्ट किया जायेगा। जहां तक 5000 टीचर्स भर्ती किए हैं उनकी बात है वे खाली पोस्टों की जगह भर्ती किए गये हैं उस समय रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ था। इन पोस्टों को भरने के बाद टीचर्स को वहीं भेजा जा रहा है जहां बच्चे अधिक हैं। स्पीकर सर, हम किसी को मुफ्त में तनख्वाह नहीं देंगे, किसी को सुविधा के अनुसार पोस्टिड नहीं करेंगे। जहां बच्चे होंगे वहीं पर टीचर्स को भेजा जायेगा। स्पीकर सर, कांग्रेस की सरकार के समय में तो एस0डी0ओ0, डी0ओ0, और बी0ई0ओ0 के आफिसों में ही 10-10 टीचर रहते थे और मुफ्त में तनख्वाह लेते थे। लेकिन हम टीचर्स को खाली नहीं बैठायेगे ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। स्पीकर सर, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बाकायदा टीचर्स को

[प्रो० सम्पत सिंह]

ट्रेनिंग दी गई है, रिफ़ेशर कोर्स दिया गया है। इन अच्छे कार्यों के लिए माने राम गुप्ता जी को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए लेकिन ये अपनी बात ही किए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

घोषणा

अध्यक्ष द्वारा

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य हाउस में मोबाईल फोन लेकर बैठे हैं वे मोबाईल फोन को या तो हाउस से बाहर रख दें या उसका स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे नव निर्वाचित विधायक श्री मलिक चंद गंभीर जी ने आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था नीचे लायब्रेरी के साथ की है इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, प्रैस के साथी भी आमंत्रित हैं और सभी अधिकारीगण भी आमंत्रित हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरावृत्त)

Amount Sanctioned by H.R.D.F. in Mewat area

*969. Sh. Nafe Singh Rathee

Sh. Ram Kumar Saini

: Will the Chief Minister be pleased to State the constituencywise total amount sanctioned by H.R.D.F. in the various constituencies of Mewat Area like Taurau, Nuh and Ferozpur Jhirka during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999 togetherwith the amount sanctioned in the above said constituencies during the period from 25-7-1999 to 31-1-2002 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : एच०आर०डी०एफ० स्कीम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए मेवात के निर्वाचन क्षेत्रों में जैसे तावड़ू, नूह तथा फिरोजपुर झिरका में 11-5-1996 से 24-7-1999 तक एवं 25-7-1999 से 31-1-2002 तक की अवधि के दौरान निम्न प्रकार से राशि स्वीकृत की गई : -

(राशि लाखों में)

निर्वाचन क्षेत्र	11-5-1996 से 24-7-1999 तक स्वीकृत राशि	25-7-1999 से 31-1-2002 तक स्वीकृत राशि
तावड़ू	218.68	1022.85
नूह	87.58	855.60
फिरोजपुर झिरका	124.09	694.99
कुल जोड़	430.35	2573.44

चौधरी नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस्० महोदय से जानना चाहूंगा कि 1991 से 1996 तक चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में इन क्षेत्रों के लिए कितनी राशि एच०आर०डी०एफ० के तहत दी गई।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि भजन लाल जी की सरकार के समय में सारा पैसा आदमपुर में ही लगता था किसी दूसरी जगह नहीं लगता था लेकिन मेरे साथी अलग से इस बारे में लिखकर मुझे दे दें, इनको पूरी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री कृष्णपाल : स्पीकर साहब, अभी सी०पी०एस० साहब ने तावड़ू नूंह और फ़िरोजपुर झिरका क्षेत्रों का आंकड़े वार ब्योरा दिया है कि एच०आर०डी०एफ० के माध्यम से वहां पर कितना-कितना पैसा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये हरियाणा प्रदेश के दूसरे विधान सभा क्षेत्रों का ब्योरा भी आंकड़े वार बतायें कि एच०आर०डी०एफ० से विधान सभा क्षेत्र वाईज कितना-कितना पैसा अलाट किया गया है। यदि यह पैसा अलाट किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि मैंने 3 विधानसभा क्षेत्रों का आंकड़े वार ब्योरा दिया है। इस बारे में मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि सभी 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जा-जा कर यह पूछा गया है कि तुम्हारे गांव में क्या तकलीफ है, क्या आपके वहां पर गलियाँ कच्ची हैं, क्या आपके वहां पर हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल और जनरल चौपाल है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी कृष्णपाल जी ने बहुत लम्बी चौड़ी डिटेल्स पूछ ली हैं। आज हमारा प्रदेश वास्तव में खुशहाली का प्रतीक है। हर तरफ से आज खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। जो आंकड़े कृष्णपाल जी ने पूछे हैं उनके बारे में बताते हुए मैं सबसे पहले विपक्ष के नेता चौधरी भजन लाल जी के हल्के से श्रुत करता हूँ। इनके क्षेत्र में वैसे तो पहले ही काफी काम हो चुके हैं लेकिन चौटाला साहब बड़े मेहरबान थे इसलिए इन्होंने सोच लिया कि वहां पर कोई कसर रह गई हो तो उसको ध्यान में रखते हुए आदमपुर में इस स्कीम के तहत 1 करोड़ 61 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला सिटी में 78 लाख 74 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। असंध के अन्दर जिसके बारे में मेरे साथी ने सभी विधान सभा क्षेत्रों का ब्योरा मांगा है यानि कृष्णपाल जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर यानि असंध के अन्दर 2 करोड़ 84 लाख 37 हजार रुपये मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार से अटोली हल्के में जहां का प्रतिनिधित्व भाई नरेन्द्र सिंह जी करते हैं, उनके हल्के में 4 करोड़ 80 लाख 66 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। (विघ्न) चौटाला साहब ने इस बात की परवाह नहीं की कि वहां का प्रतिनिधित्व विपक्ष के भाई राव नरेन्द्र सिंह जी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्र सिंह जी, अब खुश तो हैं ना।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, बाढड़ा में 8 करोड़ 2 लाख 92 हजार रुपये मंजूर किए हैं जिनमें से 8 करोड़ 95 लाख 30 हजार रुपये रितीज़ भी हो चुके हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : इसमें आप क्या कर रहे हैं, यह तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी कह रहे हैं कि यह स्कीम तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है। ये प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं इन्हें अभी तक हरियाणा रूरल डिवेलपमेंट फण्ड का पता नहीं है। इनको यह नहीं पता कि रूरल डिवेलपमेंट फण्ड क्या होता है। इनको यह नहीं पता कि सेंटर की कौन सी स्कीमें हैं और हरियाणा सरकार की कौन सी स्कीमें हैं। स्पीकर साहब, मैं हरियाणा रूरल डिवेलपमेंट फण्ड का जवाब दे रहा हूँ। (विघ्न) स्पीकर साहब, बादली में 5 करोड़ 66 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। बहादुरगढ़ में 4 करोड़ 85 लाख 58 हजार रुपये मंजूर हुए हैं। बल्लबगढ़ में 2 करोड़ 9 लाख 97 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। (विघ्न) बरवाला में 2 करोड़ 89 लाख 38 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, ये झां भी भर रहे हैं। काली टोपी वाले जय प्रकाश जी जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं वे हां भर रहे हैं। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश : सर, ये गलत कह रहे हैं। * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जायें। (शोर एवं विष्णु) जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। सी0पी0एस0 साहब, आप अपना रिप्लाय कमलीट करें।

श्री रामपाल नाजरा : स्पीकर साहब, बावल में 3 करोड़ 36 लाख 98 हजार रुपये मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा बेरी में 1 करोड़ 90 लाख 99 हजार रुपये मंजूर हुए हैं। (विष्णु)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपको बोलने का अभी मैंने कोई अधिकार नहीं दिया है।

श्री रामपाल नाजरा : भड्डकला का 97 लाख 98 हजार है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, ये लोग अपने इल्कों का विकास देख कर राजी नहीं हैं। इनकी बात हम बताते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमने इनके क्षेत्रों में इतना विकास किया, इतना पैसा दिया ये लोग इस पर भी खुश नहीं हैं। इनको तो चाहिए था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करते। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये लोग कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

12.00 बजे श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Loss suffered by Haryana Roadways

*983. श्री Suraj Mal : Will the Transport Minister be pleased to state whether the Haryana Roadways suffered any loss during the last three years; if so, the reasons thereof together with the steps taken or proposed to be taken to make it viable ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

हरियाणा राज्य परिवहन का पिछले तीन वर्षों में हानि का अस्थाई ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	वर्ष	हानि (करोड़ रुपये में)
1.	1998-99	59.64
2.	1999-2000	100.40 (अस्थाई)
3.	2000-2001	72.21 (अस्थाई)
4.	2001-2002 (अप्रैल, 2001 से जनवरी 2002 तक)	45.34 (अस्थाई)

* चयन के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हानि के महत्वपूर्ण कारण :-

1. हरियाणा में यात्रीकरण की दर देशभर में सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य परिवहन में कर से पूर्व लाभ देशभर की अन्य सभी राज्य परिवहन संस्थाओं से अधिक है।
2. वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के दौरान अपर्याप्त मात्रा में बसों को बदला गया।
3. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 01-1-98 से लागू करने तथा अतिरिक्त भंडगाई भत्तों की किस्तों की अवायगी से स्थापना खर्चों में भारी बढ़ोतरी।
4. डिजाइन व सुवीकेंट सहित विभिन्न मदों की कीमतों में बढ़ोतरी।
5. विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त/ रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान करने से हरियाणा राज्य परिवहन पर अत्यधिक भार-जैसाकि विद्यार्थी, कुछ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्रता सेनानी, विकलांग व्यक्ति, खिलाड़ी, लेखक और मान्यता प्राप्त संवाददाता इत्यादि।
6. सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु अल्प आय वाले मार्गों का संचालन।
7. परिचालन कार्य कुशलता में कमियां जिन्हें काफी हद तक ठीक किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया आगे जारी है।

हानि को कम करने हेतु उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम :-

1. हरियाणा राज्य परिवहन की पुरानी बसों को बदलने व बसों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लगभग 1200 पुरानी बसों को पहले ही पिछले दो वर्षों में बदला जा चुका है तथा 31 मार्च 2003 तक और 800 पुरानी बसों को बदलने की योजना है।
2. नई बसों की बाड़ी का डिजाइन आधुनिक, सुरक्षित तथा आरामदायक बनाया गया है। बसों के इस नये डिजाइन को आम जनता द्वारा काफी पसन्द किया जा रहा है।
3. परिचालन कार्यकुशलता में काफी सुधार लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप बेड़े की उपयोगिता, वाहन उपयोगिता व बसों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि से यातायात आय में काफी सुधार हुआ है। यह परिणाम विभिन्न कदम उठाने से प्राप्त हुये हैं जैसे कि मार्गों व समय सारणी को युक्तिसंगत बनाना; कम आय वाले अन्तर्राज्यीय मार्गों में कमी करना; राज्य के अन्दर महत्वपूर्ण मार्गों पर शटल बस सेवाएँ शुरू करना; राज्य के सभी मुख्य बस स्टैण्डों पर केन्द्रीय अग्रिम बुकिंग प्रणाली लागू करना; कई वित्तीय सुधारों को लागू करना; डिपुओं व उप-डिपुओं को तर्कसंगत बनाना; राज्य परिवहन के अमले की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य परिवहन के कुल अमले की संख्या में काफी कमी आई है यह संख्या 31 मार्च 1998, में 20985 से घटकर इस वर्ष 31 जनवरी 2002 तक 18960 रह गयी।
4. कर्मचारियों के वेतन इत्यादि तथा अन्य मदों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद खर्चों पर काफी नियन्त्रण रखा गया है, जिसके कारण हानि में काफी कमी आई है।
5. कर्मचारियों को उत्साहित करने की तरफ काफी ध्यान दिया गया है जोकि हरियाणा राज्य परिवहन की दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी से साफ दिखाई देता है। इससे राज्य परिवहन के घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। हरियाणा राज्य परिवहन की कार्यकुशलता में सुधार को देखते हुये सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन के सभी

[श्री अशोक कुमार]

पात्र कर्मचारियों को वर्ष 1998-99 का बोमस तथा वर्ष 1999-2000 व 2000-01 के लिये राज्य परिवहन के सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

Allocation of Foodgrains free of cost

*945. Sh. Ram Phal Kundu : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Central Govt. have allocated foodgrains free of cost under Sampooran Gramteen Rozgar Yojana (Food for work) to Haryana State during the year 2001-2002; if so, the district-wise details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा राज्य को वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (काम के लिए अनाज) के अन्तर्गत 70818 मिट्रिक टन खाद्यान्नों का मुफ्त आवंटन किया है। स्कीम के अन्तर्गत खाद्यान्न का जिलावार ब्यौरा विवरणी, जो कि सदन की भेज पर रखी जाती है, में दिया गया है।

क्र० संख्या	जिले का नाम	2001-2002 के दौरान एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत आवंटित कुल खाद्यान्न (मिट्रिक टन में)
1.	अम्बाला	3062
2.	भिवानी	4999
3.	फरीदाबाद	5110
4.	फतेहाबाद	3154
5.	गुड़गांव	5908
6.	हिसार	3975
7.	झज्जर	4198
8.	जीन्द	4259
9.	कैथल	3194
10.	करनाल	3417
11.	कुरुक्षेत्र	2214
12.	महेन्द्रगढ़	2942
13.	पंचकुला	2251
14.	पानीपत	2789
15.	रिवाड़ी	3080
16.	रोहतक	4703
17.	सिरसा	4134
18.	सोनीपत	3992
19.	यमुनानगर	3436
	कुल	70818

Laying of Sewerage System in Mahendergarh

*984. Rao Dan Singh : Will the Chief Minister be pleased to state :—

Whether there is any proposal under consideration of the Govt., to lay sewerage system in Mahendergarh City; if so, the time it is likely to be laid down ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्री मान जी।

Krishak Uphaar Yojana

*988. Sh. Bhagwan Sahai Rawat : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the HSAMB is implementing a scheme namely 'Krishak Uphaar Yojan', if so, the details thereof ?

कृषि मन्त्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संखु) : हाँ, श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य की सभी मण्डियों में 'कृषक उपहार योजना' 2 अक्टूबर, 2000 से प्रारम्भ की है।

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में वर्ष में दो बार ईनामी झा आयोजित किये जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में हर छः महीने में पुरस्कार कृषि उपकरणों के रूप में वितरण किये जा रहे हैं जिनकी राशि निम्न प्रकार है:-

प्रथम पुरस्कार	2	रुपये 40,000/- प्रति पुरस्कार
द्वितीय पुरस्कार	8	रुपये 25,000/- प्रति पुरस्कार
तृतीय पुरस्कार	12	रुपये 10,000/- प्रति पुरस्कार

Setting up of Rice Mill At Rania

*996 Smt. Vidya Baniwal : Will the Minister for Cooperation be pleased to state —

- whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Rice Mill by HAFED at Rania; and
- if so, the time by which the above said Mill is likely to be set up ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

- हां, श्रीमान् जी।
- हेफेड द्वारा रानिया में आगामी धान सीजन से पहले ही चावल मिल स्थापित कर दी जाएगी।

Posts of Lecturers lying vacant

*895 Shri Nafe Singh Jundla : Will the Minister of State for Education be pleased to state the number of posts of lecturers, if any lying vacant in Government Colleges in the State at present; if so, the steps taken or proposed to be taken to fill up the said posts particularly in the College of rural areas?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौधरी बहादुर सिंह) : श्रीमान् जी, सम्बद्ध सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

[चौधरी बहादुर सिंह]

राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक अमले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में 269 प्राध्यापक नियुक्त किए गये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 228 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है। यदि मार्च, 2002 तक की सेवानिवृत्तियों/पदोन्नतियों की भी गणना की जाए तो 152 अतिरिक्त महाविद्यालय प्राध्यापकों की आवश्यकता होने की सम्भावना है जिसके लिए प्रथम चरण में मांग पहले ही हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। विषयवार आवश्यकता का पता लगाने के लिए महाविद्यालयों के कार्यभार का पुनः आकलन किया जा रहा है तथा उसके बाद बकाया 76 पदों हेतु मांग आवश्यकतानुसार भेजी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की आवश्यकता पूरी की जा चुकी है। ऐसा पहले शहरी महाविद्यालयों में अधिक संख्या में तैनात शिक्षकों की युक्तिसंगत तैनाती करके किया गया है। इसके अतिरिक्त नये भर्ती किए गये प्राध्यापकों के द्वारा प्रथम तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवा करने की नीति भी सरकार ने बनाई और लागू की है।

Augmentation of Drinking Water Projects

*967. Sh. Ram Kumar Saini : Will the Chief Minister be pleased to state the number of villages districtwise, to be benefitted under the augmentation of drinking water projects in the State sanctioned by the NABARD ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान् जी, इस बारे में सूची खचन के पटल पर रखी गई है।

क्रम सं०	जिला का नाम	लाभान्वित गांवों की संख्या
1.	सिरसा	45
2.	रोहतक	14
3.	झज्जर	47
4.	कुरुक्षेत्र	97
5.	भिवानी	59
6.	जींद	32
7.	महेन्द्रगढ़	14
8.	रिवाड़ी	10
9.	गुड़गांव	31
10.	पानीपत	34
11.	सोनीपत	33
12.	कैथल	26
13.	अम्बाला	77
	कुल	519

Completion of Lohari, Pataudi and Mujjfra Minors

*963. **Sh. Ram Bir Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the time by which the construction work of Pataudi minor, Lobari minor and Mujjfra minor in the Pataudi constituency will be completed; and
- (b) the time by which the water will be released in the above said minors?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) इन योजनाओं की 31-3-2003 तक पूरा होने की सम्भावना है।
- (ख) माइनरों के पूरा होने के पश्चात् तुरन्त पानी छोड़ दिया जाएगा।

Setting up of City Police Station in Jhajjar

*1001. **Sh. Daryao Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the government to set up City Police Station in Jhajjar;
- (b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) जी नहीं, श्रीमान्।
- (ख) -

Trauma Center

*976. **Sh. Shadi Lal Batra** : Will the Minister of State for Health be pleased to state-whether the Govt. intends to start Trauma Center in the only state owned Medical College, Rohtak whose building has been constructed & completed ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डॉ० मुनी लाल रंगा) : जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Declaration of Ambala Saha Road as National Highway

71. **Sh. Anil Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to get Ambala-Saha State Highway to be declared as National Highway ;
- (b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to strengthen and widen the Ambala-Jagadhari State Highway ; and
- (c) if so, the time by which the aforesaid proposal are likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) हां, श्रीमान् जी।
- (ख) नहीं, श्रीमान् जी।
- (ग) राष्ट्रीय उच्चमार्ग घोषित करने के बारे में निर्णय भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय द्वारा लिया जाना है। अतः अम्बाला-साहा सड़क को कब तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किया जाएगा बताया नहीं जा सकता।

Setting up of 220 KV Sub-Station, Tepla

72. Sh. Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that a 220 KVA Sub-station is being set up at Tepla, Distt. Ambala;
- (b) if so, the time by which above project is likely to be got completed; and
- (c) the amount to be spent on it and the time by which Ambala Cantt. will start getting electricity supply from this Sub-station?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) तेपला जिला अम्बाला में एक नया 220 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है।
- (ख) यह उपकेन्द्र वर्ष 2002-03 तक पूरा होना संभावित है।
- (ग) इस उपकेन्द्र की अनुमानित लागत 18.66 करोड़ रुपए है तथा इससे सम्बन्धित 220 के0वी0 डी/सी अब्दुल्लापुर तेपला लाईन की लागत 6.42 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-03 में इस उपकेन्द्र के चालू होने के बाद अम्बाला कैंट इस उपकेन्द्र से तत्काल बिजली आपूर्ति प्राप्त करना शुरू कर देगा।

Repair/Strengthening of Urban Roads

73. Sh. Anil Vij : Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/strengthen the urban roads in the State; and
- (b) if so, the amount sanctioned for each district during last five years ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

- (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान सड़कों की मरम्मत/मजबूत करने के लिए राशि निम्न अनुसार स्वीकृत की गई :-

क्र० सं०	जिले का नाम	सड़कों की मरम्मत/मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई राशि (लाखों में)
1.	हिसार	400.93
2.	निवानी	708.22
3.	सिरसा	267.91
4.	फतेहाबाद	203.85
5.	करनाल	649.13
6.	कैथल	291.53
7.	पानीपत	412.93
8.	जीन्द	208.49
9.	रोहतक	558.76
10.	झज्जर	507.35
11.	सोनीपत	495.10
12.	पंचकूला	164.13
13.	यमुनानगर	616.80
14.	कुरुक्षेत्र	689.09
15.	अम्बाला	723.02
16.	गुड़गाँवा	776.47
17.	फरीदाबाद	266.22
18.	रिवाड़ी	458.68
19.	महेन्द्रगढ़	237.81
	कुल जमा	8538.41

Sample of Medicines

85. Sh. Anil Vij : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

- whether any samples of Medicines have been taken during the last five years; if so, the districtwise and yearwise details thereof;
- the number of samples out of those referred to in part (a) above have been failed, together-with the action taken in this regard ; and
- the steps taken or proposed to be taken to check the sale of spurious medicines in the State?

राज्य स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) :

(ए) हां, पिछले पांच वर्षों में जिलावार तथा सालाना, नियमित लिए गए नमूनों का विवरण अनेक्चर-I पर है।

(बी) (i) कुल 785 नमूने निम्न स्तर के तथा मिलावटी पाए गए हैं जोकि अनेक्चर -II पर दर्शाये गए हैं।

(ii) मिलावटी/सपूरियस पाए गए सभी नमूनों के मामलों में मुकदमा दायर करन के आदेश दिए हुए हैं जिसमें से 83 मामलों में मुकदमें पहले ही विभिन्न न्यायालयों में दायर किए जा चुके हैं और 38 मामलों की खानबीन की जा रही है। 338 मामलों में विभाग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियम 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत हरियाणा राज्य में स्थित औषधि निर्माताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। 325 मामले बाहर के राज्यों में स्थित उनके औषधि निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भेजे जा चुके हैं।

(iii) राज्य में सपूरियस दवाईयों के चेक के लिए निम्नलिखित पग उठाये जा रहे हैं :

(i) जिला औषधि निरीक्षकों को दवाईयों की दुकानों/आर०एम०पी०जे० से प्रति मास 12 नमूने लेने की हिदायत जारी की हुई है।

(ii) वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को भी औषधि निर्माताओं से प्रति मास पांच नमूने लेने होते हैं।

(iii) दवाईयों की दुकानों पर विशेष छापे मारे जा रहे हैं।

ANNEXURE-I

Details of samples taken District wise/year wise

Name of the District	Year 1997-98	Year 1998-99	Year 1999-2000	Year 2000-2001	Year 2001 upto December
1	2	3	4	5	6
Ambala	110	232	283	323	227
Bhiwani	96	115	123	161	29
Faridabad	109	128	236	223	215
Fatehabad	70	63	112	115	73
Gurgaon	121	157	217	227	193
Hissar	104	316	354	356	212
Jind	95	87	108	163	81

1	2	3	4	5	6
Jhajjar	60	12	-	35	134
Kuruksbetra	70	83	114	54	91
Kaithal	94	79	47	6	83
Karnai	102	149	189	160	151
Narnual	50	9	15	15	-
Panipat	106	79	128	868	102
Panchkuia	90	42	72	95	86
Rohatak	110	197	172	165	98
Rewari	86	108	136	127	94
Sirsa	90	11	120	92	39
Sonepat	216	69	148	129	93
Yamuna Nagar	96	137	139	132	132
Total	1875	2073	2713	2646	2133

ANNEXURE-II

Details of samples declared not of standard quality

Year	Sub standard	Adultrated/spurious
1997-98	135	12
1998-99	102	31
1999-2000	110	30
2000-2001	173	16
2001 upto December	144	32
Total	664	121

Details of samples declared a not of standard quality (District wise)

Name of the District	Year 1997-98	Year 1998-99	Year 1999-2000	Year 2000-2001	Year 2001 upto December
1	2	3	4	5	6
Ambala	12	20	13	23	7
Bhiwani	8	4	7	9	2
Faridabad	9	8	7	9	13
Fatehabad	-	1	-	9	9
Gurgaon	11	7	7	12	28
Hissar	20	7	28	30	19
Ind	-	3	18	8	2

[डॉ एमएलओ रंगा]

1	2	3	4	5	6
Jhajjar	-	-	-	2	5
Kurukshetra	11	9	4	3	12
Kaithal	3	5	3	1	5
Karnal	4	5	8	14	6
Narnaul	2	1	2	-	1
Panipat	8	1	6	4	2
Panchkula	8	1	5	10	4
Rohtak	19	28	17	26	10
Rewari	11	3	11	8	20
Sirsa	8	11	2	2	8
Sonepat	3	6	6	8	8
Yamuna Nagar	9	4	-	10	22
Total	146	124	144	188	183

Amount Spent on Old Age Pension

86. Sh. Nafe Singh Rathil : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the details of amount of old-age, disabled and widow pension disbursed during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002 ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (चौधरी रिसाल सिंह) : ब्योरा इस प्रकार से है :-

अवधि	वृद्धावस्था पेंशन खर्चा	विधवा पेंशन खर्चा (करोड़ों में)	विकलांग पेंशन खर्चा	कुल योग
1	2	3	4	5
(I) 1-4-1991 से 31-3-1996				
1991-92	60.18	16.40	3.62	80.20
1992-93	71.33	13.68	3.08	88.09
1993-94	54.36	13.66	3.93	71.95
1994-95	114.22	17.87	3.94	136.03
1995-96	80.14	17.84	3.96	101.94
योग	380.23	79.45	18.53	478.21

1	2	3	4	5
(II) 1-4-1996 से 31-7-1999				
1996-97	83.88	23.52	4.44	111.84
1997-98	81.82	26.89	4.66	113.37
1998-99	82.88	27.64	5.11	115.63
1-4-1999 से 31-7-1999	33.17	12.36	2.28	47.81
योग	281.75	90.41	16.49	388.65
(III) 1-8-1999 से 10-2-2002				
1-8-1999 से 31-3-2000	90.99	28.30	5.25	124.54
2000-2001	221.35	67.08	13.13	301.56
1-4-2001 से 10-2-2002	187.62	61.20	12.93	261.75
योग	499.96	156.58	31.31	687.85

Amount Spent on the Construction of Harijan Chaupals

87. **Shri Nafe Singh Rathi** : Will the Chief Minister be pleased to state —

- the constituency wise number of S.C and B.C. Chaupals constructed in the state during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th February, 2002;
- the Constituency wise number of Chaupals in the State for which the amount has been sanctioned in the "Sarkar Apke Dwar" programme?

Interim Reply

OM PARKASH CHAUTALA

D.O. No.

CHIEF MINISTER, HARYANA

Chandigarh, Dated 5th March, 2002

Subject : Unstarred Assembly Question No. 87.

Respected Speaker

Sh. Nafe Singh Rathi, M.L.A. vide Question No. 87 asked the following Question:

- the constituency-wise number of S.C. and B.C. Chaupals constructed in the State during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th February, 2002;

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(b) the constituency wise number of Chaupals in the State for which the amount has been sanctioned in "Sarkar Apke Dwar" programme?

The information regarding the number of constituency wise S.C. and B.C. Chaupals got constructed in the above said period will have to be collected from the field offices in the State, and collection of requisite information in such a short span of period is not possible. It is, therefore, requested that atleast six weeks time may kindly be granted so that desired information is collected from the field agencies.

Yours Sincerely,

Sd/-

(Om Prakash Chautala)

Shri Satbir Singh Kadian,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,

Road Constructed by H.S.A.M.B.

88. **Shri Nafe Singh Rathi:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the constituency wise details of new roads in Kilometers constructed, reconstructed and repaired by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the villages of Haryana during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, 1st April 1996 to 31st July, 1999 and 1st August, 1999 to 10th February, 2002 togetherwith the expenditure incurred thereon ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में सड़कों के निर्माण, पुनः निर्माण तथा मरम्मत व इन पर खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :-

अवधि	नई सड़कों का निर्माण		पुनः निर्मित सड़कें		मरम्मत की सड़कें	
	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)
1-4-91 से 31-3-96	1950.74	71.40	-	-	385.61	3.72
1-4-96 से 31-7-99	903.81	44.59	8.19	0.30	1249.28	22.21
1-8-99 से 10-2-02	2819.96	208.53	2.80	0.17	3677.95	137.55

निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार करने हेतु समय व श्रम की तुलना में इससे विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

School upgraded in the State

89. **Sh. Nafe Singh Rathi** : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

- (a) the yearwise number of Schools upgraded in the State during the period form 1st April, 1991 to 31st March, 1996.
- (b) the total number of new rooms constructed by the Govt. in the Govt. Schools referred to in part (a) above;
- (c) the constituency wise number of rooms constructed in the Govt. Schools by the Haryana Govt. during the period from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002 respectively, together-with the Schools upgraded during the said period in the State ;
- (d) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Government School in the State during the next academic Session especially in Bhadurgarh Constituency ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) राज्य में वर्षवार 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1996 तक जिन विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है।

1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
161	152	79	258	458

(ख) राजकीय विद्यालयों में 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1996 समय के दौरान नये निर्मित किये गये नये कमरों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है :-

1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
101	166	162	253	297

(ग) हरियाणा सरकार द्वारा विद्यालयों में विद्यान सभा क्षेत्रवार नये निर्मित किये गये कमरों की संख्या 1 अप्रैल, 1996 से 31 जुलाई, 1999 और 1 अगस्त, 1999 से 10 फरवरी, 2002 तक अनुबन्ध "क" अनुसार है 4/96 से 7/99 के दौरान स्तरोन्नत किये गये विद्यालयों की संख्या 736 तथा 8/99 से 10-2-2002 तक स्तरोन्नत किये गये विद्यालयों की संख्या 349 है।

(घ) राज्य में वर्ष 2001-2002 के दौरान 91 विद्यालयों को स्तरोन्नत किया गया था। सह विद्यालय नये सत्र से कार्य आरम्भ कर देंगे। 146 विद्यालयों का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें से 9 विद्यालय (3 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, 3 माध्यमिक से उच्च विद्यालय तथा 3 उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) बहादुरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में है।

[चौधरी बहादुर सिंह]

निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार कमरें बनाने की सूचना निम्नानुसार है।

अनुबन्ध-क

जिला							कुल	
अम्बाला	अम्बाला शहर	अम्बाला छावनी	नरगज	नारायणगढ़	मुलाना			
4/96 से 7/99	29	03	13	03	05		53	
8/99 से 10-2-02	08	01	10	15	17		51	
कुरुक्षेत्र	थानेसर	पेहवा	शाहबाद					
4/96 से 7/99	05	-	02	-	-		07	
8/99 से 10-2-02	02	-	01	-	-		03	
भिवानी	भिवानी	बवानी	बाढ़डा	दादरी	तोशाम	लोहारू	मुण्डाल	
	खेड़ा						खुर्द	
4/96 से 7/99	06	11	04	05	16	-	06	48
8/99 से 10-2-02	-	12	09	-	-	09	-	80
रोहतक	रोहतक	मझम	कलानीर	हसनगढ़			किलोई	
4/96 से 7/99	02		07	07	02		05	23
8/99 से 10-2-02	-		04	05	02		07	18
फरीदाबाद	फरीदाबाद	मेवला	बल्लबगढ़	पलवल	हसनपुर	दधीन		
		महाराजपुर						
4/96 से 7/99	2	-	2	8			25	37
8/99 से 10-2-02	15	8	6	4	6		21	60
झज्जर	झज्जर	बेरी	बादली	साल्हावास	बहादुरगढ़			
4/96 से 7/99	28		11	10	28		1	78
8/99 से 10-2-02	22		18	63	11		10	124
नारनौल		नारनौल		अटेली	महेन्द्रगढ़			
4/96 से 7/99		1		1	-			2
8/99 से 10-2-02		12		20	5			37
पानीपत		पानीपत		समालखा	नौलथा			
4/96 से 7/99		11		70	29			107
8/99 से 10-2-02		18		53	29			100
रिवाड़ी		रिवाड़ी		बावल	जाहूसाना			
4/96 से 7/99		41		100	56			197
8/99 से 10-2-02		4		26	6			100

8/99 से 10-2-02	15	8	6	4	6	34	60
हिसार	हिसार	हांसी	आदमपुर	धिरायें	बरवाला	नारनौद	
4/96 से 7/99	-	43	5	105	21	13	187
8/99 से 10-2-02	4	28	16	49	41	16	154
फतेहाबाद	फतेहाबाद	भदकलां	टोहाना	रतियां			
4/96 से 7/99	5	14	1	-			20
8/99 से 10-2-02	32	21	66	27			146
सिरसा	सिरसा	रोड़ी	डबवाली	दड़वाकलां	ऐलनाबाद		
4/96 से 7/99	-	-	-	-	-	-	-
8/99 से 10-2-02	10	181	65	16	44		306
यमुनानगर	यमुनानगर	छछरीली	सदौरा	जगाधरी	रादौर		
4/96 से 7/99	3	11	-	9	1		24
8/99 से 10-2-02	41	20	63	40	32		196
करनाल	करनाल	नीलोखेडी	इन्द्री	जुंडला	धरीन्डा	असन्ध	
4/96 से 7/99	7	7	8	2	-	9	33
8/99 से 10-2-02	14	20	6	15	20	37	112
गुड़गांव	गुड़गांव	सोहना	पटौदी	मूंह	फिरोजपुर	सावड़ू	
					झिरका		
4/96 से 7/99	6	9	6	4	3	3	31
8/99 से 10-2-02	5	5	6	-	-	2	18
सोनीपत	सोनीपत	राई	रोहट	कैलाना	गोहाना	बरोदा	
4/96 से 7/99	15	3	15	44	3	1	81
8/99 से 10-2-02	-	16	18	39	12	6	91
पंचकुला	कालका						
4/96 से 7/99		37					37
8/99 से 10-2-02		-					
जीन्द	जीन्द	नरथाना	सफीदों	जुलाना	उथाना	कलां	
4/96 से 7/99	24	10	8	15	11		68
8/99 से 10-2-02	6	31	25	3	7		72
कैथल	कैथल	राजौद	कलापत	पाई	गुहला	चीका	पुण्डरी
4/96 से 7/99	7	8	16	6	7	3	47
8/99 से 10-2-02	8	9	13	16	4	8	58

Closure of Bus Depot Charkhi Dadri

90. Sh. Jagjit Singh : Will the Minister for Transport be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Depot of Haryana Roadways, Charkhi Dadri has been closed; if so, the reasons thereof togetherwith date of its closure ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : दादरी डिपो को बन्द नहीं किया गया है, इसे केवल 1 अप्रैल, 2001 से भिवानी डिपो का उप-डिपो बनाया गया है। यह निर्णय भिवानी, दादरी व झज्जर क्षेत्र के लोगों को और अच्छी परिवहन सेवार्सें प्रदान करने तथा विभाग की परिचालन एवं वित्तीय कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये लिया गया था।

Repair of Samaspur-Imlota Road

91. Sh. Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Road from Samaspur to Imlota via Bhagvi located in Dadri Sub-division ; and
- (b) if so, the time by which the said road referred to in part (a) above is likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) हाँ, श्रीमान् जी। कार्य प्रगति पर है।
- (ख) गांव सरूपगढ़ में अतिक्रमण हटाने के 3 मास के अन्दर सड़क की पूरी तरह से मरम्मत कर दी जाएगी।

Leakage in Kitlana Distributory

92. Sh. Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to check the leakage from Chakhi to Iktayrapura Head of Kitlana distributory, Dadri Sub Division; if so, the time by which the said leakage is likely to be checked ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : गांव चरखी से इकतयारपुरा तक कितलाना रजबाहे में रिसाव जोड़ों के बूने का कारण है। घन की उपलब्धता पर जोड़ों को भरने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

श्री रामपाल भाजरा : अध्यक्ष महोदय, आज तो इन लोगों को सहयोग करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, दो महान विभूतियां इस संसार से चली गई हैं, मैं आपकी अनुमति से उनके लिए हाउस में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप प्रस्ताव करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह सदन 7 मार्च, 2002 को शहीद हुए गांव बहलम्बा रोहतक के सिपाही श्री राजबीर राठी और 9 मार्च, 2002 को गांव कोसली जिला रिवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी श्री शय सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से एक वीर सिपाही तथा स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीधरजी भजन झाल (आदमपुर) : लीडर ऑफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा दुखी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। इस शोक प्रस्ताव को पास किया जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपने आप को तथा अपनी पार्टी को भी इसमें शामिल करता हूँ तथा इस शोक प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मੈम्बर्ज, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उसके साथ अपने को जोड़ता हूँ और शोक संतप्त परिवारों को विधान सभा की ओर से रैजोल्यूशन भेज दिया जाएगा। अब मैं आप सभी से अनुरोध करना कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आप अपनी-अपनी सीटों पर दो मिनट के लिए मौन के लिए खड़े हों।

(इस समय हाउस ने दो मिनट मौन खड़े हो कर श्रद्धांजलि अर्पित की)

ध्यानकर्षण प्रस्ताव

पंजाब क्षेत्र में एस0वाई0एल0 केनाल को पूरा करने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, M.L.A. regarding completion of S.Y.L. in Punjab Territory. I admit it. He may read his notice.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिए जाने तथा अब पंजाब सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका (रिज्यू पटोशन) रद्द होने से हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिसके लिए हरियाणा सरकार बर्खाई की पात्र है तथा सारा प्रवेश खुशियां मना रहा है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरियाणा की वर्षों से प्यासी धरती की प्यास बुझेगी। किसान खुशहाल होगा। राज्य का बहुमुखी विकास होगा। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के नेताओं द्वारा रोजाना दिए जा रहे ब्यानों तथा सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में गव-निर्वाचित कांग्रेस सरकार तथा उनके मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए विरोधी स्टैंड से हरियाणा की जनता के मन में शंका तथा भय व्याप्त है। यहाँ यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आज से पहले जब भी हरियाणा के हितों का मामला आया है, केंद्र सरकार ने हमेशा पंजाब राज्य का पक्ष लिया है। जो लोगों में अधिक चिन्ता का कारण बना हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ? सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा-

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा और माननीय सदस्य ने यह जो जानना चाहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब के नेताओं द्वारा इस नहर विरोधी स्टैण्ड ले हरियाणा की जनता के मन में भय व्याप्त है तथा केन्द्र सरकार ने सदा पंजाब के लोगों का साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2002 को जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसमें यह निर्देश दिए हैं कि पंजाब सरकार 15 जनवरी, 2002 से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर इस लिंक नहर का निर्माण पूरा करे तथा केन्द्र सरकार को भी यह निर्देश दिए हैं वह अपने सर्वैधानिक दायित्व का पालन करते हुए यह देखें कि यदि पंजाब सरकार एक वर्ष के अन्दर-अन्दर नहर का निर्माण पूरा नहीं कर पाती है तो केन्द्र सरकार अपनी ऐजेन्सियों द्वारा शीघ्रतिशीघ्र इस नहर का निर्माण पूरा करवाए। अध्यक्ष महोदय, यह शंका बेबुनियाद है कि केन्द्र सरकार हरियाणा के हितों की अनदेखी करेगी तथा पंजाब सरकार का साथ देगी। वर्तमान केन्द्र सरकार का रवैया हरियाणा विरोधी कभी नहीं रहा है। सरकार को पूरा विश्वास है कि मौजूदा केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को बिना किसी भेदभाव के पूरा करेगी। मैं इस मामले में प्रधान मंत्री जी से मिला-था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष का समय पंजाब सरकार को इस कार्य को पूरा करने के लिए दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानने के लिए पंजाब सरकार व केन्द्र सरकार दोनों ही बाध्य हैं। हमें केन्द्र सरकार से इस विषय पर पूर्ण न्याय की आशा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है तथा इस पर समय-समय अपना दायित्व निभाती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर का जो हिस्सा हरियाणा में पड़ता है उसका सर्वेक्षण पूरा करा लिया है। इस कार्य पर 12 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। पश्चिमी यमुना नहर के आऊटफाल से मुलक तक मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हरियाणा के हिस्से में नहर के हिस्से के निर्माण कार्य को अति शीघ्र पूरा किया जा सके। मैं माननीय सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार हरियाणावासियों के हितों की रक्षा हर सम्भव कीमत पर करेगी तथा सदा अपनी क्षमता एवं शक्ति के अनुसार हमेशा इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखेगी ताकि हरियाणा प्रदेश की भूमि पर रावी व्यास का पानी अतिशीघ्र पहुंच सके। हमें आशा है कि हरियाणा के लिए यह नहर एक वरदान साबित होगी और हरियाणा को शीघ्र ही समृद्धशाली एवं खुशहाल बनाएगी।

श्री अध्यक्ष : अब अनिल विज अपनी अप्पीयेंटी पूछेंगे।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, आप बैठें। पहले अनिल विज ने अपनी सप्लीमेंट्री पूछनी है।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, हम भी इस बारे में अपनी बात कहना चाहते हैं।

* * * * *

श्री अध्यक्ष : ये अब जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि कालिंग अटेंशन मोशन पर कौन सप्लीमेंट्री पूछ सकता है ?

श्री अध्यक्ष : जिसका नोटिस होगा वहीं अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकता है।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, और सदस्य भी इस बारे में अपना सवाल पूछ सकते हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, ये इस मामले में सीरियस नहीं है अगर ये सीरियस होते तो ये भी इस बारे में अपना कालिंग अटेंशन मोशन या कोई दूसरा नोटिस देते लेकिन ये इस बारे में कुछ भी हाउस में लेकर नहीं आए हैं। (शोर एवं व्यवधान) They are not serious.

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : They have missed the train इसलिए स्पीकर सर, ये अब खड़े हो रहे हैं इनकी इस मामले में कोई सीरियसनेस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमीशन के बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सम्पत सिंह जी हर बात पर वैसे ही खड़े हो जाते हैं। ये घटिया बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, यह घटिया शब्द हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अभी आपको इस बारे में पता नहीं है कि किस समय पर क्या बोलना चाहिए। हालांकि आपको इस बारे में बहुत बताया गया है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप इनकी क्लास लिया करें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर साहब, यह बहुत सीरियस इशु है आप रूल 73-ए के तहत इस मामले पर शोर्ट नोटिस डिक्लेशन करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये लोग आपकी फिशखदिली का फायदा उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब इनकी पार्टी के सारे लोगों ने काली टोपी पहन रखी है तो भजनलाल जी काली टोपी क्यों नहीं पहन रहे हैं। ये भी काली टोपी पहनकर दिखाएं। क्या यह टोपी इनके सिर के मुताबिक छोटी हो गयी है ? (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, क्या मैं बोल सकता हूँ ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, पहले आप ही बोलें।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि प्रदेश के हित में और सरकार के हित में क्या है, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा। अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक साल में एस0वाई0एल0 नहर पंजाब बनाएगा।

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, आप तो फिर उसी बात पर आ रहे हैं मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ और बात कहेंगे। इसलिए अब आप बैठें।

चौधरी भजनलाल : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, अब आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो भजनलाल जी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस कालिंग अटेंशन मोशन पर केवल अनिल विज ही अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मैं अपनी रिप्लाइ दूंगा उस समय मैं एस0वाई0एल0 के मुद्दे को पूरी तरह से उजागर करूंगा उसके बाद किसी की कोई शंका नहीं रह जाएगी।

चौधरी भजनलाल : अगर ऐसा है तो अच्छी बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें इस तरह के मोशन का जबाब समय पर तो दिलवा दिया करें ताकि हम उसको पढ़ सकें। इसको पढ़ने के बाद अगर कोई सदस्य उस पर कुछ पूछना चाहें तो वह पूछ सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस कालिंग अटेंशन मोशन का जबाब आ गया है इसलिए अब आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इसका जबाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : इसका जबाब हाउस में दे दिया गया है। जिसका कालिंग अटेंशन मोशन है उनके पास इसका जबाब है और वे इस बारे में सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। इसलिए अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) अनिल विज पूछ रहे हैं उनको पूछने दें मैंने तो सोचा था कि दो तीन दिन की छुट्टी थी कुछ तो असर हुआ होगा। आपने इस बारे में बात करनी हो तो मेरे चेंबर में आकर अलग से बात कर लें।

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, आज हमने काली टोपी पहन रखी है उसके बारे में आपने पूछा नहीं कि क्या लगा रखी है। * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने काली टोपी का जिक्र किया। गांधी जी की सफेद टोपी को कांग्रेस के काले कारनामों ने काला कर दिया। परमात्मा इन भाइयों को सदबुद्धि दे इन्होंने टोपी तो अपनाई है अब ये गांधी जी के पदचिन्हों पर भी चलना शुरू कर दें।

चौधरी भजन लाल : रोष प्रदर्शन के लिए काली टोपी लगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई ऐतराज नहीं है चाहे आप काले कपड़े पहनें। आप काला कुर्ता पजामा भी पहनेंगे तो भी मैं बिचकुल नहीं उतरवाऊंगा। विज साहब, आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, सभी मैम्बर में बड़ा रोष है। (शोर एवं व्यवधान) जो सात मैम्बर सस्पेंड थे वे आज बोलेंगे। इसलिए एक दिन बजट के लिए आगे बढ़ाएँ।

श्री अध्यक्ष : बी०ए०सी० की रिपोर्ट के हिसाब से आज चीफ मिनिस्टर साहब ने रिप्लाय देनी है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चौधरी भजनलाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में किया जाए।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हमें रिप्लाय की कॉपी दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको रूल-73 पढ़कर सुनाता हूँ-

"There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question."

आपने दिया नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है।

श्री डॉ० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप बड़े ही काबिल और फिसखदिल स्पीकर हैं।

श्री अध्यक्ष : थलो अच्छा हुआ आपको सद्बुद्धि आ गई। (शोर एवं व्यवधान) आप भी काबिल बनो। चौधरी बंसी लाल जी की छोटी सी पार्टी है दो मैम्बर हैं दोनों बोले हैं बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे कुछ और बात कर रहे हैं ये कुछ और बात कर रहे हैं सलाह तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, श्री अनिल विज जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं और बहुत ही लोक महत्त्व का और पब्लिक हित का मुद्दा through Calling Attention Motion इस सदन में उन्होंने उठाया है स्पीकर सर, सरकार की तत्परता देखिये कि आज सुबह उन्होंने अपना Under Rule 73 Calling Attention Motion का नोटिस दिया और उसके तुरन्त बाद कोई टाईम लिये बिना और हाउस का एक सैकिण्ड भी गवायें बगैर सरकार ने उसका रिप्लाय दिया। क्योंकि सारा प्रदेश इस बारे में चिन्तित है और एस० वाई०एल० प्रदेश की लाईफ लाईन है। इस लिए सरकार ने इमीजियेट उसका रिप्लाय दिया और माननीय विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि रूल 73 का रिप्लाय सर्कुलेट नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आपने रूझिंग दी है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

प्रो० सम्मत सिंह : स्पीकर सर, मेरी बात तो सुनिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्मत सिंह जी, मुझे बोलने दीजिये।

प्रो० सम्मत सिंह : स्पीकर सर, मेरी बात तो सुनिये। दलाल साहब, मैं स्पीकर साहब की परभीक्षण से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये। क्यों आप प्वायंट ऑफ आर्डर का मिसयूज कर रहे हैं ?

डॉ० रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ ही मिस यूज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस यूज नहीं है बल्कि आप तो खुद कंप्यूज हो। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने भी अण्डर रूल-73 के तहत एस०वाई०एल० के बारे में नोटिस दिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर डिसकशन जरूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप अगर इतने चिन्तित होते तो आप यह नोटिस पहले देते। आपने 12 बजकर 22 मिनट पर यह नोटिस दिया है यह नोटिस आपको पहले देना चाहिये था पहले आप कहां गए थे? अब आप बैठ जाइये। इस विषय पर डिबेट शुरू हो चुकी है अगर आप इतने चिन्तित होते तो पहले नोटिस देते (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर डिसकशन जरूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने कालिंग अटेंशन नोटिस समय पर दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर डिसकशन जरूर होनी चाहिये। आप इसको रद्द नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : अगर रद्द करने के काबिल होगा तो रद्द करेंगे और मंजूर करने के काबिल होगा तो मंजूर भी करेंगे। आप मौका चूक गये। अब अनिल विज को मौका दीजिये।

प्रो० सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन लोगों का अपना दायित्व बनता था अगर इनको इतनी चिन्ता होती तो ये कोई मोशन देते। माननीय सदस्य श्री अनिल विज सदन में कोई मोशन लेकर आये हैं तो उनकी बात को पूरा-सुन नहीं रहे हैं बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाय आ रहा है उसके बाद माननीय सदस्य अगर प्रदेश के हित में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं यदि उनके दिमाग में कोई शंका है तो वह शंका भी प्रदेश के हित में होगी और उसका जवाब भी प्रदेश के हित में होगा। चौधरी भजन लाल जी भी एस०वाई०एल० के बारे में जितना बोलना चाहते थे बोले, उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी भी उस विषय पर जितना बोलना चाहते थे, बोले, जो उन्होंने अपनी बात कहनी थी वह तो कह दी।

बाकी सदस्य भी इस बारे में बोले थे, जो बात उन्होंने कहनी थी उन्होंने भी कही। इसके बाद बजट भी आयेगा उस पर भी बोलने का समय दिया जायेगा अगर उस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जहां तक मोशन का सवाल है मोशन पर सवाल या तो वह सदस्य पूछे जो मोशन लेकर आये हैं। वे इतने सीरियस थे तभी इसको समय पर लेकर आये हैं। स्पीकर सर, आपने रूल 73(2) के बारे में अपनी रूलिंग दी है लेकिन मैं रूल 73(1) के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा In Rule 73(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, it is mentioned

"A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date".

ब्रीफ स्टेटमेंट गवर्नमेंट उस पर दे not less than Chief Minister उसके बारे में हाउस के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरन्त उस बात का एकदम जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा सरकार की तत्परता और क्या होगी ? श्री अनिल विज जो कालिग अटेंशन मोशन लेकर आये हैं उसके बारे में वे सीरियस थे और अगर वे उस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनको सवाल पूछने दें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे सकें and that will be in the interest of the State and in the interest of public, Sir.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सरकार का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि इतने शॉर्ट समय में कॉलिंग अटेंशन मोशन ऐडमिट की गई और सरकार उसका उत्तर लेकर आई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट ऑफ ऑर्डर है। मैं भी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर रक्षा हूँ इसलिए मैं इनको पढ़वाना चाहता हूँ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्मत सिंह : क्योंकि मैम्बर के लिए मुख्यमंत्री महोदय का ब्यान आ गया है और वह रिकार्ड हो गया है। सिर्फ जो मैम्बर पूछता है उसके लिए ही रिप्लाय है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : * * * * *

श्री० जय प्रकाश : * * * * *

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह कादियान और जय प्रकाश बरवाला की कोई बात रिकार्ड न की जाए। हाउस में स्टेटमेंट आ चुकी है, उसे आपने गौर से सुना इसलिए इसे दिमाग में रखें। मैं त्राजायज किसी को नहीं बोलने देता और जायज बात सबकी सुनता हूँ। इसलिए आप दोनों बैठें। रूल 73 (1) और (2) पढ़कर देखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिटार्, ये बीच-बीच में मुझे इन्ट्रूट कर रहे हैं। Please listen me. Do not encroach upon my rights. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में बहुत ही

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अनिल विज]

सुस्पष्ट निर्णय दिया है लेकिन अगर पिछले इतिहास देखें कि आज तक जब भी हमारे और पंजाब के बीच में चाहे वह सीमा विवाद रहा हो, या पानी के मामले की बात रही हो या शाह बानो कमीशन की रिपोर्ट हो या इन्दिरा समझौता हो या राजीव लॉगोवाल समझौता रहा हो, मैथ्यू कमीशन रहा हो या पानी के बारे में, चाहे तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से को हुई सहमति की बैठक हो, जब-जब भी जिस-जिस ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया, पंजाब ने उस निर्णय को कभी भी नहीं माना है। देश में ऐसे भी अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और लोगों ने न माना हो तो केन्द्र सरकार ने बिल लाकर उस निर्णय को निरस्त करवाया, शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था लेकिन केन्द्र सरकार ने उसके विरुद्ध निर्णय लेकर उसको निरस्त किया। इसलिए लोगों की शंका निर्मूल नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सबके बावजूद भी पिछले इतिहास को देखते हुए कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करता और जैसा कि पंजाब सरकार के नेताओं के ब्यान रोज दूसरों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के बारे में आते हैं वहीं उनके खुद के रोज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ब्यान आ रहे हैं। यदि फिर भी पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल नहीं करती तो हमारी सरकार किस प्रकार से अपने को तैयार कर रही है यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ? स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहर बनाने का निर्णय दे दिया क्या पानी का भी निर्णय कर दिया कि कितने एम०ए०एफ० पानी हमें मिलेगा। (विज) तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि पंजाब में कितने किलो मीटर नहर बनी हुई है और कितनी अधूरी है और जो अधूरी है वह एक साल में बन सकती है या नहीं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा न सिर्फ सम्मानित सदस्य श्री अनिल विज को बल्कि पूरे सदन को इस अहम विषय से अवगत करवाना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पंजाब को मानना ही पड़ेगा। आज तक कोई ऐसी मिसाल देखने और सुनने में नहीं आई कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी ने न माना हो। जहां तक पानी का संबंध है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इंटरिम रिपोर्ट 3.83 एम०ए०एफ० पानी की आ गई है कि हमें 3.83 एम०ए०एफ० पानी मिलेगा। इस बारे में मुकम्मल रिपोर्ट बाकी है। वह भी आयेगी इस मामले में मेरे माननीय साथी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे की बजाए एक और अहम मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्दा है वह प्रदेश स्तर का नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर जुड़ा हुआ है पंजाब के फैसले से पहले यह फैसला आ जायेगा और एक साल के अर्से में निश्चित रूप से यह नहर बन जायेगी अब तो साल भी नहीं है 15 जनवरी से 365 दिन का (एक साल का) समय निश्चित हुआ था, अब तो एक साल से भी कम समय रह गया है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस समय पंजाब के सभी राजनैतिक दल कह रहे थे कि रिव्यू करेंगे, वह रिव्यू भी खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में भी रिव्यू खारिज हो गया इसलिए इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक साल के अंदर-अंदर नहर बन जायेगी इसलिए सारी तैयारी हम पहले से ही कर रहे हैं। हम चौधरी बंसी लाल जी की तरह कमीशन खाने के लिए पहले काम नहीं करवा रहे बल्कि जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाये।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

चौधरी बंसी लाल द्वारा-

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रसन्न एक्सप्लेनेशन है। मेरा सबमिशन यह है कि कमीशन मुख्यमंत्री जी खाते है, मैं नहीं खाता। ये कह रहे हैं कि इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, यह रिपोर्ट फाइनल है। इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को ये बदल नहीं सकते, उसमें क्लैरीफिकेशन कर सकते हैं।

वक्तव्य - उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनराारम्भ)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी इसी सदन में दुर्भाग्य से यहां बैठा करते थे और मैं विपक्ष में बैठा करता था। उस वक्त भी एक बात मैं कहता था कि चौधरी साहब इंजीनियर इन चीफ श्री पाठक साहब के कहने के बावजूद भी आपने नहर का काम गोदबलावा से शुरू क्यों किया ? अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में इस नहर का काम टेल से शुरू करवाया। ये सीनियर मैनबर हैं क्या इनको मालूम नहीं कि ड्रेन का काम टेल से शुरू होता है और नहर का काम मुड से होता है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। इंजीनियर ने इन्हे सलाह भी दी थी कि नहर का काम मुड से शुरू किया जाये लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, जितनी नहर पंजाब में बननी थी वह पंजाब सरकार ने बनवानी थी उसका कमीशन इन्हें नहीं मिलना था इसलिए इन्होंने जो नहर हरियाणा में बननी थी, उसको बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका कमीशन इनको मिलना था। इन्होंने उस समय करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिये।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, न मैंने कमीशन खाया और न मैंने कमीशन खाना सीखा। कमीशन खाने का काम मुख्यमंत्री जी का है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, स्वयं चौधरी बंसी लाल जी परसों अपनी बात की कंट्राडिक्शन कर गये। पहले जब हम कहते थे कि हरियाणा में पहले नहर नहीं बननी चाहिए उस समय ये कहते थे कि नहर बननी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। इनकी कौन सी बात ठीक है। उस समय हम कहते थे कि ये कमीशन खाने के लिए नहर टेल से बनवा रहे हैं और अब ये उल्टा हमें कह रहे हैं कि मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। जिस समय चौधरी देवी लाल जी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गये थे उस समय बंसी लाल जी कहते थे कि गलत किया, कोर्ट में तो 10 साल लग जायेंगे फिर इन्होंने इसकी सराहना की कि बहुत अच्छा किया। ये अपनी एक बात पर नहीं रहते।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नहर की मुरम्मत न करने के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने परसों वहां कहा है और यह रिकार्ड में है। मैं तो यहां नहीं था लेकिन चौधरी भजन लाल जी थे, ये ही बता देंगे।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो हम भी कहते हैं कि पहले मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। जब तक पंजाब में नहर नहीं बनती तब तक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे चौटाला साहब ने बंसी लाल जी को कमीशन खाने के बारे में कहा वैसे ही अब ये कमीशन खाना चाहते होंगे। जब पंजाब में नहर बन जाये उस समय मुरम्मत शुरू करनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में नहर 95 प्रतिशत बन चुकी है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वह सारी नहर टूट गई है दोबारा बनानी पड़ेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक साल के अंदर-अंदर पंजाब के अंदर नहर बन जायेगी इसका हमें विश्वास है। उससे पहले हम अपने यहां मुरम्मत भी करेंगे क्योंकि बंसी लाल जी ने यह नहर पहले बनवा दी और अब उसमें गादड़ बिया गये हैं उन्होंने सारी नहर खोद डाली है, अगर उसकी मुरम्मत नहीं करेंगे तो पानी कैसे चलेगा। इसके अतिरिक्त हम भाईनर डिस्ट्रीब्यूट्रियां भी बनायेंगे ताकि एक साल बाद दक्षिणी हरियाणा को भी दना-दन पानी मिल सके।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से 1 साल के अंदर यह नहर बननी है। इस एक साल की अवधि में से अब तक 60 दिन तो निकल चुके हैं और अभी तक इस पर कोई काम भी शुरू नहीं हुआ है। (विघ्न) इस बारे में कहना यह है कि आपको चाहे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन लेनी पड़े, अगर पंजाब में इस नहर पर 3-4 महीने में काम शुरू नहीं होता तो आपको आगे की सोच कर कोई बात करनी होगी।*****
(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं होगी।

चौधरी भजन लाल : मैंने क्या गलत बोल दिया है जो रिकार्ड नहीं करोगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : यह आपकी क्या समझ है।

श्री अध्यक्ष : आप में अच्छी समझ है। आप में अच्छी समझ दिख रही है, आप में अच्छी समझ लग रही है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, अगर ये लोग समझदार होते तो ये लोग इस जगह न बैठे होते। (शोर एवं विघ्न) भजन लाल जी इसमें आपको क्या चिन्ता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नहर को पंजाब सरकार ने बनाना है। पंजाब में आपकी सरकार है। आप भी प्रयास करो कि ये जल्दी नहर बनवा दें। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : पहले आपके बादल की सरकार थी तो उस वक्त आपने इसे क्यों नहीं बनवा लिया। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हां, पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने इस नहर के बनवाने का काम बी0आर0ओ0 के सुंपर्द कर दिया था। (शोर एवं विघ्न) फिर बाद में जब आपकी सरकार आई तो आपने इसको विदग्ध कर लिया। (शोर एवं विघ्न)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : आपने कब बी०आर०ओ० को सुपर्द कर दिया था। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी जब उप प्रधानमंत्री थे, चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री थे और मैं मुख्यमंत्री था तो उस वक्त हमने इस नहर को बनवाने का काम बी०आर०ओ० के सुपर्द कर दिया था और इस पर काम शुरू हो गया था। बाद में आपकी सरकार आ गई और आपने उसको विदग्ध कर लिया। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उस वक्त तक तो कोई फैसला नहीं हुआ था कि (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप यह बताएं कि आपने इसे उस वक्त विदग्ध क्यों किया। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिये। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको यह काम विदग्ध नहीं करना चाहिए था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी बैठ जाएं। अब गवर्नर एड्रेस पर मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाइ देंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमारे जो मैम्बरज सदम में उपस्थित नहीं थे, उनको अब आप गवर्नर एड्रेस पर पहले बोलने का मौका दे दें, उसके बाद सी०एम० साहब अपना रिप्लाइ दे देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपकी पार्टी को जितना समय देना चाहिए था वह स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : हमारे मैम्बरों को पहले आप बोलने का समय दे दें। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अब कोई समय नहीं मिलेगा। (शोर एवं विघ्न) बी०ए०सी० की मीटिंग में आप उपस्थित थे। उस में बाकायदा तय हुआ था कि मैंने 11 तारीख को रिप्लाइ देना है।

चौधरी भजन लाल : ठीक है, आपने रिप्लाइ देना है। मेरा कहना यह है कि जिन मैम्बरों को निकाल दिया गया था पहले उनको आप बोल लेने दें फिर आप अपनी रिप्लाइ दे देना (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप उस मीटिंग में थे। मैंने 11 तारीख को रिप्लाइ देना है। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आप मैम्बरों को बाहर निकाल दें और फिर बोलने न दें, क्या यह ठीक है। (शोर एवं विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर ये गलत काम करेंगे तो यह स्पीकर का काम है कि उनको रखें या न रखें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आपकी पार्टी पोजीशन के हिसाब से गवर्नर एड्रेस पर बोलने के लिए आप लोगों के 130 मिनट बभते थे जबकि आप लोग 132 मिनट बोल चुके हैं। आपके मैम्बर निकलने के बावजूद भी आप लोग गवर्नर एड्रेस पर पहले ही 132 मिनट बोल चुके हैं (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : जी नहीं, उनको गलत तरीके से हाउस से निकाला गया था। (शोर एवं विघ्न) पहले उनको आप बुलवायें, फिर थै रिप्लाइ दे लेंगे। (शोर एवं विघ्न)

आवाजें : नहीं, नहीं, नहीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं कैसे। यह तो रिकार्ड है। हमारे पास अलग-अलग समय है कौन कितनी देर बोला। (शोर एवं विघ्न) आपके जो मैम्बर थे उनको बोलने का पूरा समय दिया और सदन का समय भी बढ़ाया गया था। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : इन्होंने बस्ते बांध लिए हैं, ये वाक आऊट करेंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आपने गलत तरीके से उनको निकाला था। जो नाम हमने आपको दिए हुए हैं उनको आप बुलवायें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपके जो मैम्बर थे, उन सभी को बुलवाया गया था। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अब ये जायेंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : मंत्री जी क्या ये 7 मैम्बर बोलेंगे नहीं। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : ये अपने बस्ते बांध रहे हैं, ये जायेंगे, ये वाक आऊट करेंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : ये सीनियर मैम्बर हैं, इनको आप बोलने दें। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने बाहर जाने के लिए बस्ते बांध लिए हैं। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, ये 10-10 मिनट बोल लेंगे। ये 10-10 मिनट में अपनी बात कह लेंगे। (शोर एवं विघ्न) ऐसे कैसे बात बनेगी !

प्रो० सम्पत सिंह : आप भागेंगे।

चौधरी भजन लाल : नहीं, हम भागेंगे नहीं। हम यहीं रहेंगे। पहले आप हमारे साथियों को बोलने दीजिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। कांग्रेस पार्टी के सदस्य पहले ही 132 मिनट बोल चुके हैं। जो सदन में थे, हमने उन सबको बोलने का समय दिया। सदन चलता रहा लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी बोलने के लिए नहीं रह रहा था। (शोर एवं विघ्न)

आवाजें : हम तो आपको भी आगे बुलवाना चाहते थे लेकिन आप भी दौड़ गये थे। (शोर एवं विघ्न)

फैटन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें आप बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप भी चले गए थे (शोर एवं व्यवधान) अभी बजट भी पेश होना है और एप्रोप्रियेशन बिल भी आने हैं आम जन पर बोल लेना।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप अखबार पीने रखें, आप हाउस में अखबार नहीं दिखा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) नो-नो आप अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। कैप्टन साहब, मैं आपको वार्न करता हूँ। जय प्रकाश जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइये। आपकी पार्टी के नेता ने बोलने के लिए जिलने सदस्यों के नाम दिए थे वे सभी सदस्य बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठें। हाऊस का समय बढ़ाया गया था, जो समय बिजनैस ऐडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट में निर्धारित हुआ था उसमें आपके 130 मिनट बनते थे लेकिन आपकी पार्टी के लोग 132 मिनट बोल चुके हैं इसलिए अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग बोल नहीं सके वे भी बोल सकते थे लेकिन आप लोग हाऊस में रहे नहीं (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : हमें तो आपने नेम कर दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मेरा कसूर नहीं था। (शोर एवं व्यवधान) यह मेरा कसूर नहीं था। जिसने गलती की उसको गलती की सजा मिली। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजनलाल जी भी गलती का अहसास करते हैं। जो गलती करेगा उसको गलती का दण्ड तो मिलेगा ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन 7 मैम्बरों को आपने नेम कर दिया था उनको तो बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आपके पीछे जो आपके मैम्बर खड़े हैं आप उनको तो बिटाएँ। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आपकी बात कोई मानता तो है नहीं ये लोग तो आपको नेता ही नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप अपने पीछे देखें कि क्या हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

श्री चौधरी भजन लाल : जो मैम्बर बोले नहीं और आपने उनको नेम कर दिया और हाउस से बाहर निकाल दिया आज वे अपनी बात तो कहेंगे।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नो-नो आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठें (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं आप इनको बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे ?

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : नो-नो, आप बैठें। इतने लोगों में से मैं किस-किस की बात सुनूँ (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी, आप इनको कंट्रोल करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मैम्बर्ज को बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे (शोर एवं व्यवधान)* * * *

श्री अध्यक्ष : आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप का यह कोई तरीका है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाएं। जय प्रकाश जी, मैं आपको फिर वार्न करता हूँ आप अपना बिहेवियर ठीक करें। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। राव नरेन्द्र सिंह जी, आप हाऊस में नहीं थे आप सदन से चले गए थे आप कमी बाथरूम में जाकर छिप जाते थे और कमी लोबी में चले जाते थे। (विध्वन) आप 2.30 बजे सदन में नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये सदन में थे।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी झूठी गवाही नहीं दिया करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये हाऊस में नहीं थे। आप राम किशन फीजी से पूछ लें उस वक़्त चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी सदन में थी। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी आप इनको अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहें। आप इनको सदन में बात करने की और बैठने की ट्रेनिंग दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्ज को आपने बोलने का मौका नहीं दिया है क्या आप उनको बोलने का मौका देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी 7 तारीख को आपने जिन-जिन मैम्बर्ज की लिस्ट दी थी उन सभी को बोलने का मौका दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) सभी पार्टीज को बोलने का मौका दिया गया है। अभी बजट भी पेश होना है उस पर भी आपकी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने का मौका दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका देंगे या नहीं। आप हमें हां या न में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इन सबको बिठाएं।

चौधरी भजन लाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम सब अपनी सीटों पर बैठते हैं आप हमें यह बताएं कि हमारे मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका देंगे या नहीं। आप हमें हां या न में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

वाक आउट्स

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे उन सात मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं जिनको पिछले सप्ताह सदन से सस्पेंड कर दिया गया था इसलिए हम एज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आपके मैम्बर्ज को पूरा टाईम दिया गया है, अब आप बैठ जाएं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप सस्पेंड मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो हम भी एज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। लगता है कि आप भी उनकी तरह वाक-आउट करना चाहते हैं। अब सी0एम0 साहब ने रिप्लाय देनी है इसलिए आप बैठ जाएं। लगता है आपमें अब अक्ल ठीक आसी है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आपने मेरी पार्टी को बोलने के लिए टाईम नहीं दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे गवर्नर ऐड्रेस पर अपनी बात कहने का मौका दीजिए। मेरे इलाके के लोगों की बात मुझे यहां पर कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी-अपनी पार्टी की कोई कदम ही नहीं करते। आप ही हाऊस से वाक-आउट करके चले गए थे। कभी आप खुद चले जाते हैं और कभी आपका आचरण ऐसा होता है कि मुझे आपको हाऊस से निकालना पड़ता है। अब भी आपने ऐसा ही आचरण शुरू कर रखा है। जब सबको बोलने का मौका दिया जा रहा था उस समय आप हाऊस में नहीं थे। आपकी पार्टी सात तारीख को हाऊस में नहीं थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप मुझे केवल पांच मिनट का बोलने के लिए समय दे दें। अगर आप मुझे बोलने के लिए समय दे देंगे तो मेरे इलाके के लोगों की समस्याएं भी यहां पर दर्ज हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप अब बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, जब आपने कांग्रेस पार्टी को बोलने का समय दिया है, बीजेपी को बोलने का समय दिया है, बंसीलाल जी की पार्टी को बोलने का समय दिया है और इंडीपेंडेंट्स को भी बोलने का समय दिया है तो मेरी पार्टी का भी डक है मेरा भी डक है कि आप मुझे बोलने के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जो हाज़िर हैं उनको ही बोलने का टाईम मिलेगा। पलवल में तो आपको बोलने के लिए टाईम नहीं दिया जाएगा। अब आपने टोपी भी उतार ली है इसलिए अब आप बैठ जाएं। I warn you.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आपकी यह भी कोई बात है।

श्री अध्यक्ष : सही तो बात होती है। जब आपका ज्वहार ही ऐसा है तो यही बात होती है। अब जो भी दलाल साहब बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठ जाएं। अब आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें। अब आप हाऊस का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? अगर आपका यहां से जाने का मन हो तो आप अपनी इच्छा पूरी करें। अन्यथा आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है उस समय पर वही मामला टेक-अप होगा। अब आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं कोई अन-पार्लियामेंट्री बात तो नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। जब समय आएगा तब आपको अपने इलाके के लोगों की बात कहने के लिए समय दिया जाएगा। अब आप वैसे ही हाऊस का समय खराब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाऊस का कितना कीमती समय है, कितना पैसा विधान सभा के संचालन में लगता है। कितने ऑफिसर्स यहां पर बैठे हैं लेकिन आपकी वजह से हाऊस का सारे का सारा काम रुका हुआ है। आप इसमें दिक्कत डाल रहे हैं। आप बैठें।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एक मात्र माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री चन्मत सिंह : स्पीकर साहब, हम यह बात बार-बार कह रहे हैं कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस किसम की भूमिका अपोजीशन के लोगों द्वारा यहाँ पर निभायी जा रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर साहब, आपने अपने चैम्बर में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी थी और उस मीटिंग में विपक्ष के नेता भी उपस्थित थे और सदन के नेता भी उसमें उपस्थित थे। मुझे सारे हाऊस को बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपने यह मीटिंग बुलाई तो पहली बार उसमें युनानीमसली इस बारे में फैसला हुआ था वरना तो पहले यह होता था कि एक जॉयसैटिंग नोट विपक्ष का हुआ करता था लेकिन हरियाणा प्रदेश में पहली बार बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में विपक्ष के नेता ने भी यह माना कि गवर्नर ऐंड्रेस पर डिसकशन के लिए तीन फुल डे रखे जाएंगे और चौथे दिन मुख्यमंत्री जी का उस पर रिप्लाय होगा। स्पीकर सर, अगर ये लोग सीरियस होते तो विधान सभा में पहले दिन से ही कंट्रीब्यूशन करते लेकिन इनका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं था। आपने इनको स्वयं हाऊस से नहीं निकाला लेकिन जब इन्होंने हाऊस को चलाने नहीं दिया तब मजबूर होकर आपने उनको हाऊस से निकाला। आपने तो उनको बार-बार काल किया कि अगर उनमें से कोई भी बोलना चाहता है तो बोल लें लेकिन ये नहीं बोले। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब आपने उस दिन हाऊस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया था तो विपक्ष के नेता ने कहा था नो-नो! स्पीकर साहब, यह भी असेम्बली के इतिहास में पहली बार होगा कि रूनिंग पार्टी समय बढ़ा रही है और विपक्ष समय घटाने की बात कर रहा है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा उस दिन भजनलाल जी ने और इनकी पार्टी ने नो-नो कहा था। अगर ये सीरियस होते तो ये टाईम बढ़ाने की बात करते। उस दिन पांच लोग गवर्नर ऐंड्रेस पर पूरी तरह से बोले। हरियाणा विकास पार्टी के दोनों मैम्बर्ज भी गवर्नर ऐंड्रेस पर बोले। स्पीकर सर, मैं इस बारे में रिकार्ड की बात करके बताना चाहूँगा कि आपने उनको कितना टाईम बोलने के लिए अलॉट किया था। रूनिंग पार्टी को 300 मिनट का टाईम अलॉट किया था और वे आपके सामने 150 मिनट बोले। केवल आधा समय हमारी पार्टी ने लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग ज्यादा बोले। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपने 130 मिनट का टाईम दिया था और वे 132 मिनट बोले हैं और फिर भी आप हाऊस को ऐक्सटेंड कर रहे थे लेकिन ये बोले कि हमें मूख लगी है हम जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र अपने पेट की भूख के लिए इनको प्रदेश की भूख की परवाह नहीं है। केवल रोटी खाने के लिए पहले चले गए। स्पीकर साहब, हमारी सहयोगी पार्टी सी0जे0पी0 को आपने 40 मिनट का टाईम दिया था और वे इतना बोले हैं, जिन तीन का नाम था वे पूरी तरह से बोले थे और बाकी मैम्बर्स से भी आपने बोलने के लिए पूछा था उसके बाद एच0वी0पी0 के लिए 15 मिनट का टाईम रखा गया था और दिए गए टाईम से अधिक समय तक बोलने देने के बावजूद वे आज वाक-आउट करके गए हैं चौधरी बंसी लाल जी को वाक आउट करते समय थोड़ा बहुत तो महसूस करना चाहिए था उनको बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था और वे 40 मिनट बोले थे लगभग तीन गुना समय दिया गया। यह भी कहा गया कि और समय लेना चाहें तो ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको याद

[प्रो० सम्मत सिंह]

होगा फिर भी मैं याद कराना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता श्री भजन लाल जब बोलकर बैठ गए तो आपने भी इनको कहा था और मैंने भी कहा था कि बोलना चाहें तो और टाईम दे दें तो इन्होंने कहा था कि मैं बोल लिया मुझे इतना ही बोलना था। अध्यक्ष महोदय, आर०पी०आई०, एन०सी०पी० और बी०एस०पी० के लिए दस-दस मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इनके दो मेंबरों ने तो कंट्रीब्यूट किया नहीं था। मैं बी०एस०पी० के सदस्य को शाबाशी देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के टोटल टाईम में से वे दस मिनट के स्थान पर बत्तीस मिनट बोले। इससे पता चलता है कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है? इंडिपेंडेंट्स के लिए 70 मिनट का समय निर्धारित था और वे 83 मिनट बोले हैं सबको पूरा टाईम मिला है। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जवाब आना था। जवाब में सच्चाई और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और उसको ये साथी सुनना नहीं चाहते थे। जब बोलते हैं तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है उसकी वजह से केवल अखबारों में वाक-आउट का छप जाए इसलिए वाक-आउट कर गए हैं। इनका ये वाक-आउट बाकायदा निंदनीय है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरासम्म)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानित सदस्यगण, हम पिछले चार दिनों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़ा शानदार और तथ्य से परिपूर्ण अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को राज्य में हो रहे विकास के कार्यों की जानकारी मिली। मैं पूरे सदन के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करूँगा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अभिभाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी एक बात कहता था और आज अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष बैठ नहीं है। असलियत यह है कि इस प्रदेश में सुदृढ़ विपक्ष है ही नहीं। स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रणाली में मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है लेकिन आज जो विपक्ष इस सदन में है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वह किसी मामले में सीरियस नहीं है। केवल मात्र अखबार की सुखियों में आने के लिए इस प्रकार के अनर्गल प्रचार करने में जुटे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद पहला अधिवेशन जब शुरू हुआ तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ और संख्या के आधार पर उस पर चर्चा शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, चर्चा शुरू होने से पहले सारा का सारा विपक्ष सदन से वाकआउट कर गया। अगली दफा फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाने में ये कितने सीरियस थे यह भी आप को मालूम 13.00 बजे हैं। इनकी पूरी संख्या ही नहीं थी सदस्यों की संख्या के अभाव में वह प्रस्ताव भी गिर गया। अध्यक्ष महोदय, आपने इस पद की गरिमा को कितने अच्छे ढंग से कायम रखा, यह मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरे प्रदेश के लोग इस बात की सराहना करते हैं। एक पुरानी परम्परा जो आजादी मिलने के बाद से शुरू की गई थी। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के बाद आपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर नई परम्परा कायम की थी और एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में आपने पूरे सदन को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया है। आपने किसी सदस्य को वार्निंग नहीं दी, किसी को नेम नहीं किया, किसी को निकाला नहीं बल्कि

आपने तो बाकायदा विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए कहा और विपक्षी सदस्य बाथ रूम में जाकर छिप जाया करते थे जैसा कि श्री सम्पत सिंह जी ने कहा आपने जब इनको बोलने का मौका दिया तो यह कह कर सदन से भाग जाते थे कि हमें तो भूख लग रही है। आप सदन का समय बढ़ाते रहे और वे सदन से भागते रहे। इससे ज्यादा अटपटी बात और क्या होगी। इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये उसमें भी इनको रूलज रेगुलेशन का ज्ञान नहीं था। कानून कायदे पढ़े नहीं और उसका नतीजा यह निकला कि 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाना था वह नहीं दे पाये और उनका प्रस्ताव गिर गया अब की बार यमुनानगर की हार की छाप मिटाने के लिए शुरू से ही इन्होंने मन बनाया हुआ था कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, वे आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये। आपकी फिरोखदिली की दाद देनी पड़ेगी कि आपने फौरन यह कहा कि जब सदन को मेरे अन्दर विश्वास ही नहीं है तो मैं सबसे पहले सदन का विश्वास मत अर्जित करके ही इस कुर्सी पर बैठूंगा। विपक्ष का प्रस्ताव आपने मंजूर करके उस पर चर्चा के लिए कहा तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और जो इस सदन का बेशक्रीमती समय था, वह भी इन्होंने बर्बाद किया। आपके पद की गरिमा को बिगाड़ने की किस हद तक इन्होंने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आपकी पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि विपक्ष के सदस्य आपकी कुर्सी तक पहुंच गये आपकी शान में किस किसके अलफाज इस्तेमाल किये, उनको दोहराते हुये हमें शर्म महसूस होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने पीठ करके इस कुर्सी पर बैठकर अपने आप अध्यक्ष भी बन गये और एक-दूसरे मੈम्बर के खिलाफ कागून की किताब फेंकते रहे। इस प्रकार का महा प्रदर्शन प्रजातान्त्रिक प्रणाली में शायद किसी सदन में नहीं हुआ होगा। इस देश की रियासत भी हैं और ईस्टर्न स्टेट भी हैं जहां अगर किसी को विरोध प्रकट करना हो तो वे लॉबी में जाकर विरोध लिख कर देते हैं। इस प्रकार की हरकत और कहीं नहीं होती। जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया और आपने फिर भी बहुत ही सब्र से काम लिया। खासतौर से एक कांग्रेस की महिला सदस्य ने तो सीट पर और बैंच पर सनेत जूतों के बैठकर इस पूरे सदन की गरिमा को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन चूंकि महिला संशक्तिकरण वर्ष था आपकी इस बात के लिए पूरा सदन प्रशंसा करेगा कि आपने फिर भी उसके खिलाफ किसी प्रकार का ऐक्शन न लेने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जोर-शोर से ये प्रचार किया करते थे यमुनानगर के उपचुनाव के बारे में बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया था। चुनाव का माहौल बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की गई थी और यह चर्चा की जा रही थी कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जायेगी। बहुत शोर मचता था इस बात पर मुझे गालिब जी का एक शेर याद आ रहा है

" बड़ी खबर गरम थी, गालिब के उर्दंगे परखने,

देखने हम भी गये थे, पर तमाशा न हुआ !"

बहुत शोर मचाया करते थे आखिर जाकर उनकी हालत यह हो गई कि सत्ता का खाब लेने वाले लोग जो कहते थे कि सत्ता पक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो जायेगी वे 21 से 20 होकर रह गये। गिनती उनकी उल्टी होनी शुरू हो गई क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। यमुनानगर के उपचुनाव में जहां विकास के बहुत काम हो रहे थे वे पहले से ही तयशुदा थे जो विकास के काम थे वे 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हो रहे थे फिर भी ये भाई चुनाव

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आयोग के समक्ष जाकर रोजाना इस बात की आपत्ति दर्ज कराते थे कि सरकार फलों जगह फलों काम करा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये किसी मामले में भी सीरियस नहीं हैं। इनका बार-बार अविश्वास प्रस्ताव ले आना इनकी एक पुरानी आदत बन गई है और फिर ये वाक आउट दर्ज कराकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं इन्हें सरकार की बदली हुई लोकप्रियता से बहुत चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष में हुआ करते थे तो हम तो इस बात के लिए इंतजार किया करते थे कि हमें बोलने के लिए कुछ अवसर मिले, हम खुश हुआ करते थे। लेकिन आज जब सदन का अधिवेशन बुलाया जाता है तो इनको बुखार आता है यह सोचकर कि अब सदन में जाना पड़ेगा, इस सदन में क्या कहेंगे, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। यही लोग जो इस बात के लिए आपत्ति किया करते थे कि वचैश्चन आवर क्यों खत्म किया जाए। पिछली बार भी जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो कह रहे थे कि वचैश्चन आवर को समाप्त करके पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बर्चा की जाए और आज ये इस बात को भूल गए हैं और इसीलिए आज इनकी यह हालत हो गई है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जनहित के इतने काम किए हुए हैं कि पूरे के पूरे प्रदेश में किसी भी गांव में आज अगर जाया जाए तो जगह-जगह पर विकास के कार्य होते दिखाई देंगे। सरकारें पहले भी थी लेकिन पहले काम नहीं होते थे और इसलिए काम नहीं होते थे क्योंकि जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई सत्ता में बने लोग डकार जाया करते थे और अब जब ऐसे लोगों जिन्होंने जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को दबाने का प्रयास किया है, के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होते हैं तो इनको आपत्ति होती है और ये प्रैस के पास जाते हैं, कभी महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाकर कहते हैं कि बदले की भावनाओं के कारण हमारे खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के, इस स्टेट के पूरे ट्रस्टी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश की सम्पत्ति की देखभाल करें और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए जनतांत्रिक प्रणाली को कायम रखते हुए 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत इस प्रदेश का बहुमुखी विकास करने का काम हमने किया है। चौधरी बंसीलाल जी जो अब सदन में उपस्थित नहीं हैं एक बात कहते हुए हाउस से चले गए कि ये काम हमारे किए हुए हैं, वे काम हमारे किए हुए हैं। बिजली के मामले में चौधरी बंसीलाल जी होते तो मैं उनको बताता, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे वक्त में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों में आमके और सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि चौधरी बंसीलाल के शासन काल में केवल मात्र 188 मेगावाट बिजली साढ़े 3 साल के अर्से में अधिक पैदा हुई। जब मैं विपक्ष में था तो इसी सदन में मैंने बंसीलाल जी को कहा था और हमने सदन में इसका पूरा विरोध किया था। उन्होंने पानीपत का दूसरे नम्बर का यूनिट 110 मेगावाट का चालू किया। अध्यक्ष महोदय, आप तो पानीपत जिले में रहते हैं, पानीपत का दूसरे नम्बर का यूनिट ए0बी0बी0 जर्मन कम्पनी के साथ साज बाज करके करोड़ों रुपये का उनको ठेका देकर कि इससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा उसको खुलवा दिया और आज साढ़े 4 साल हो गए हैं उस प्लांट की मशीनरी खुले में पड़ी है। वहां 50-60 करोड़ रुपये का सामान पड़ा है और 300 करोड़ रुपये का हमारा उसमें नुकसान हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने भी एक नम्बर की यूनिट खुलवाई और मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा और सदन इस बात को सुनकर प्रसन्न होगा कि एक नम्बर की यूनिट खोलकर उसको ठीक करने का काम किया गया है और उस पर मात्र 5-6 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। जहां उन्होंने 110 मेगावाट की

दूसरी यूनिट का 100 करोड़ का ठेका ए0बी0बी0 कम्पनी को दिया था। वहीं हमने पानीपत की दूसरी यूनिट को भी 5-6 करोड़ रुपये में ही ठीक करवाया है और उससे बिजली की क्षमता बढ़ी है। इन्होंने 300 करोड़ रुपये तो उस पर खर्चा कर दिया इसके अलावा जितना उत्पादन होना चाहिए था और जितना लाभ मिलना चाहिए था उससे भी पूरा प्रदेश वंचित हो गया है। हमने अपने अर्द्धशताब्दी के शासनकाल में 621 मेगावाट बिजली पैदा की है। बंसीलाल जी कह कर रहे थे कि मेरे वक्त में यह हुआ है, वह हुआ है। बंसीलाल जी हर मौके पर कहते हैं कि एस0वाई0एल0 नहर मैंने खुदवाई, इतनी बिजली मेरे वक्त में पैदा हुई। चौधरी जगननाथ जी, जो आज इस संसार में नहीं है, कहा करते थे कि तोशाम का पहाड़ भी तुने बनवाया, लाल किला भी तुने बनवाया। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के पावर प्लांट से 143 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां 146 मेगावाट बिजली भी हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई। पानीपत की 210 मेगावाट की छठी यूनिट भी हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई। भाखड़ा की 15 मेगावाट और सलाल प्रोजेक्ट की 17.2 मेगावाट, टनकपुर की 1.3 मेगावाट, चभरा प्रोजेक्ट की 58.7 मेगावाट, ऊंचाहार की 23 मेगावाट, राजस्थान अणु विद्युत केन्द्र इकाई से 12.50 मेगावाट कुल मिलाकर 621.10 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के वक्त में पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि आज के दिन बिजली की बहुत जरूरत है। बिजली के बिना काम नहीं चल सकता। चाहे खेती हो, उद्योग हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो हर क्षेत्र में बिजली की अति आवश्यकता है इसलिए हम बिजली के अधिक उत्पादन के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पानीपत की रिफाइनरी से भी बिजली का मामला तय किया है। चौधरी बंसी लाल जी अब यहां बैठे नहीं हैं उन्होंने शंका व्यक्त की थी कि पानीपत की रिफाइनरी से हमारा मामला तय हुआ है या नहीं? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनसे हमने 380 मेगावाट बिजली लेने का एग्रीमेंट किया है और इस बिजली के साथ-साथ उनको हमने यह भी साफ-साफ लिखा है कि वहां उनके साथ लगते इलाके को वे करोड़ों रुपये की सुविधाएं देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट्स जो 250-250 मेगावाट की हैं उनको भी 11वीं पांचसाला योजना में शामिल कर लिया है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कन्सलटेंट मुकदर हो गया और बड़ी तेजी से हम उस काम को शुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक साथी कह रहे थे कि हम दो साल में बिजली पैदा कर देंगे। अब उनको ज्ञान तो है नहीं कि बिजली का चाहे हाईडल प्रोजेक्ट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे गैस बेरुड प्रोजेक्ट हो कम से कम 32 महीने का समय प्रोजेक्ट तैयार होने में लगता है। अध्यक्ष महोदय, हम बिजली की कमी को समझते हैं और इसीलिए हम प्रयासरत हैं। हम तो यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट को भी जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं ताकि अधिक बिजली उत्पन्न हो। अध्यक्ष महोदय, गैस बेरुड प्रोजेक्ट पर आधारित तीन संयंत्र 500-500 मेगावाट के बारे में भी हमने केन्द्र से एम0ओ0यू0 साईन किया है और हम चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी तैयार हो जायें तथा प्रदेश को अधिक बिजली मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, बिजली की दिक्कत को समझते हुए हम हमारी जितनी भी श्रुति मिलें हैं उनकी बगल से और खोई से भी बिजली पैदा करना चाहते हैं ताकि सैकड़ों मेगावाट बिजली उनसे भी पैदा हो सके और बिजली की कमी को पूरा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हम एक तरफ तो बिजली का उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास बिजली की कमी होते हुए भी हमने दूसरे प्रदेशों से महंगे दामों में बिजली लेकर किसानों को सस्ते दामों पर दी है और इसका जीता-जागता सबूत है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। अध्यक्ष

[श्री औष प्रकाश चौटाला]

महोदय, कांग्रेसी साथी आज यहां हम बैठे नहीं हैं उनकी सरकार के वक्त में 20 या 25 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल में जाता था और हमारे समय में 68 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल में देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पैदावार इसी वजह से बढ़ी है कि चाहे पानी हमारे पास थोड़ा है लेकिन हमने उस पानी को किसानों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की है, हमने अपनी नहरों की मरम्मत करवाई है। अध्यक्ष महोदय, हमने पंजाब की सरकार को भांखड़ा नहर की मरम्मत के लिए, जिस बरतन में पूरा पानी नहीं पहुंचता था उसकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपये दिया लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिए इनके समय में पानी कहां से आता ? अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में जहां हमने बिजली बढ़ाने का प्रयास किया है वहीं हमारी सोच यह है और आज हम फख से कह सकते हैं कि हमने आज करोड़ों रुपये के बिजली के बकाया बिलों को लोगों से वसूल किया है। हमने लोगों को प्रेम से प्यार से समझाया है लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में भजन लाल जी लोगों को गोलियों से मरवाते थे फिर भी ये एक पैसा वसूल नहीं कर पाये थे। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्षी भाई लोगों में प्रचार करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं कि तुम बिजली का बिल अदा न करो। लोगों की सभाओं में जाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं और लोग इनको अपनी सभाओं में आने नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय, लोग यदि कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेसी उसमें शामिल होते हैं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों को कांग्रेसियों से नफरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं लोगों को हमारे प्रति रोष हो सकता है लेकिन हम उस रोष को दूर करने के लिए किसानों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। हमने लोगों को राहत दी है और लोगों को समझाकर राह-राज पर लाने का प्रयास किया है तथा लोग आज बकाया बिजली के बिल अदा कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट हैं जो उनको बहका कर उनको गलत रास्ते पर ले जा करके उनको गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। हम लोगों को सुविधा प्राप्त करा सकते हैं लेकिन लोगों के हितों के साथ यदि कोई खिलवाड़ करके राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास करेगा तो हम उनके साथ सख्ती से निपटने में सक्षम हैं। हम जहां लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं वहां अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो हम उनसे भी निपटने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जहां पहले 2590 मेगावाट बिजली थी आज बढ़कर 3211 मेगावाट हो गई है। हम प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। यहां पर कांग्रेसी पार्टी के लोग और चौधरी बंसी लाल जी और दूसरे लोग एक बात बार-बार कहा करते हैं कि जब ये लोग विपक्ष में थे तो चौटाला रोज कहा करता था कि बिजली के बिल मत भरो। स्पीकर साहब, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम बिना पैसे के बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो 8 फरवरी, 2000 को मैंने रिलीज किया था उसमें यह साफ कह दिया था कि बिजली हम बिना पैसे के नहीं दे पायेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि हम पूरी बिजली दें। अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी, 2000 के अखबार में यह बात छपी हुई है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारे द्वारा लोगों को बरगलाया जाता था कि बिजली के बिल मत दो। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी यहां पर बैठे नहीं हैं। अब वे यहां से उठ कर चले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का एक ब्यान जो अखबार

में छपा है, ये लोगों को क्या कहते हैं इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा। ये लोगों को कहते थे याशि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कहते थे, इस बारे में उनका ब्यान 24 अगस्त, 2000 का है। वे कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार झूठे वायदे कर रहे हैं और जब भी उन्हें लागू करने की बात आती है तो आचार संहिता को हथियार बना लिया जाता है। ये विचार आज जिले के कलिंगा गांव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने व्यक्त किये। हुड्डा ने अपने ब्यान में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को बिजली व पानी मुफ्त उपलब्ध करवाया जायेगा और साथ ही खुशी माफ की जायेगी। जो लोग यह बात कहते थे, आज वे उस बात से भुनफिर होते हैं और उल्टा इल्जाम हमारे खिलाफ लगाते हैं जबकि हमारी सरकार का एक फैसला है कि हम लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के पक्षधर हैं। इसके अलावा हर स्तर पर केवल मात्र बिजली के मामले में नहीं बल्कि सिंचाई आदि के मामले में भी लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं। हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माईनर नये सिरे से चालू की है। जो माईनर आदि टूटी हुई थी या जो गलत बनी हुई थी उनको तोड़कर उनका लेवल ठीक किया है। हमने नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इस साल इतना भयानक सूखा होने के बावजूद भी हमने किसानों को पूरा पानी दिया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में आगे आने वाली गेहूं की फसल बम्पर क्राप के रूप में होगी और बड़ी भारी मात्रा में होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात के लिए आश्चर्य करना चाहूँगा कि आज किसान को बड़ी चिन्ता है कि सरकार गेहूं की फसल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार ने गेहूं की सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर नहीं की है। इस बारे में हम शीघ्र ही केन्द्र सरकार से जा करके सम्पर्क करेंगे और किसानों का एक-एक दाना खरीदा जायेगा और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देगे।

अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 का एक बड़ा अहं मुद्दा था। एस0वाई0एल0 नहर हरियाणा के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है और खास करके दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जब इस नहर का पानी पहुंचेगा तो हमें 500 करोड़ रुपये प्रति साल का लाभ होगा और 4 लाख से अधिक एकड़ रकबा सहाराब होगा। हमने इस नहर को बनवाने का निरंतर प्रयास किया है। एस0वाई0एल0 नहर बनवाने की शुरुआत चौधरी देवी लाल जी ने की थी। चौधरी देवी लाल जी ने ही सबसे पहले इसके लिए भूमि अधिग्रहण की थी। चौधरी देवी लाल जी ने पंजाब सरकार को 1 करोड़ रुपया दे करके इस पर काम शुरू करवाया था। ये लोग बार-बार इल्जाम लगाते हैं कि बादल साहब के साथ इनकी दोस्ती है इसलिए एस0वाई0एल0 के मुद्दे को टरकाने का काम करते रहे। चौधरी देवी लाल के प्रयासों से ही नहर शुरू हुई थी। चौधरी देवी लाल जी ने ही इसकी शुरुआत की थी और पंजाब की सरकार ने जब इसके न बनाये जाने के लिए अड़चन डालने का काम किया तो चौधरी देवी लाल जी ही इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ले करके गए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चौधरी बंसी लाल जी को बताया था और अब फिर वे माँके पर हैं नहीं। चौधरी बंसी लाल जी ने 19 दिसम्बर, 1991 को विधान सभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था कि चौधरी देवी लाल जी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहां पर 10-12 साल उसका फैसला नहीं होगा और यह मामला लटक जाएगा जल्द से जल्द यह तैयार हो सकती थी। आज वे लोग कहते हैं कि यह हमारा प्रयास था जबकि कांग्रेस की सरकार में चौधरी बंसी लाल जी ने वह केस विदर्रा कर लिया था और 1982

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

में हम फिर से इस मामले को कोर्ट में ले कर गए थे। हमने इस केस की पूरी पैरवी की। आज हमारी उसी पैरवी का यह परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला हमारे पक्ष में दिया। यह नहर हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है और वे लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। मैंने विज साहब की कॉलेज अटेंशन मोशन में भी इस बात को बताया था और मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूँ कि हर सूरत में नहर बनेगी और अब उसे कोई रोक नहीं पायेगा (इस वक्त मेजें थपथपाई गई) पंजाब की सरकार को यह नहर बनानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक बार यह बात कही थी कि जब कभी भी पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनेगी उस सरकार को यह नहर बनानी पड़ेगी। क्योंकि यह सुप्रीमकोर्ट का फैसला है उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हमें केन्द्र सरकार तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चौधरी बंसी लाल जी को पहले भी इस बात के लिए कहते थे और आज फिर हम कहते हैं कि नहर पहले टेल पर से बनवा दी और उसका परिणाम यह निकला कि पंजाब में जो नहर बननी थी वह नहीं बन पाई जबकि हमारे एरिया में नहर बन गई। अगर उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने इन्जीनियर इन चीफ श्री पाठक की बात मान ली होती तो हमारी यह नहर कभी की बन कर तैयार हो चुकी होती और हरियाणा आज देश का नम्बर दो प्रदेश होने की बजाए नम्बर एक का खुशहाल प्रदेश होता लेकिन इन लोगों की वजह से यह नहर नहीं बन पाई थी। अगर शुरू में उस वक्त यह नहर बना दी गई होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी थी लेकिन केवलमान कमीशन खाने के लिए टेल से नहर बनवा कर तैयार कर दी। अध्यक्ष महोदय, हैसनी इस बात की है कि जब हम यह कहते थे कि यह टेल से नहीं बननी चाहिए टेल की बजाए मुड़ से बननी चाहिए तब इन्होंने इसको जबरदस्ती बनाने का काम किया था और अब इस मामले में बंसी लाल और भजन लाल दोनों मिले हुए हैं कि अब यह नहीं बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब एक साल के अन्दर-अन्दर नहर बनेगी तो उसमें हमारी नहर की मुरम्मत करने में भी समय लगेगा उसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूटीज़ और उनके आउटलेट्स बनाने में भी समय लगेगा। हम एक मिनट का समय भी जाया करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्योंही हमें पानी मिलेगा त्यों ही पानी किसान के खेत की सिंचाई करेगा ताकि प्रदेश के किसान की पैदावार बढ़ सके। क्योंकि आज हमारे पास पानी की कमी है और जब तक हमें पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक पूरी पैदावार नहीं होगी इसलिए हम सारी ही तैयारी कर रहे हैं। दूसरे कामों को रोक कर भी हमें उसको पहले बनाना होगा क्योंकि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक खास मुद्दा और है जिस पर यहां पर चर्चा हुई। उस दिन मैं हाउस में नहीं था खासतौर पर खनन और पहाड़ के मुद्दे को लेकर चौधरी बंसी लाल जी ने भी चर्चा की थी और दूसरे लोगों ने भी चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय, खान को ओपन ऑक्शन में लेने का निर्णय हमने किया। चौधरी बंसी लाल जी जब इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे और इस सदन के सदस्य माननीय श्री करतार सिंह भडाना जी ने उस वक्त सुझाव दिया था कि उसका सबसे अच्छा हल यह है कि इन खानों को ओपन ऑक्शन कर दी जाए ताकि सरकार के खजाने में अधिक रैवेन्यू आ सके। लेकिन उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने यह बात नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के सदस्य की बात को मानकर हमने ओपन ऑक्शन करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि इससे हमारे खजाने में पैसा ज्यादा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, जिस पहाड़ को खान का जिक्र किया गया है वह केवल मात्र 52 लाख रुपये में नीलाम होता था लेकिन अब सरकार को लगभग आठ करोड़ रुपये ओपन ऑक्शन में उसका मिला है। जो लोग उसका विरोध

कर रहे थे उस लोगों ने भी उस की बोली दी हुई है। 6 करोड़ 51 लाख की बोली देने वाले उसका इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यह केवल मात्र लाखों में जाया करती थी। अध्यक्ष महोदय, निगाना के पहाड़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा। चौधरी बंसी लाल जी इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं। चौधरी बंसी लाल के टाईम में वह पहाड़ 54 लाख रुपये में नीलाम हुआ था। कांग्रेस की सरकार के वक्त में नाके लगाने का काम हुआ था लेकिन आज ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं जबकि उन्होंने खुद भी नाके लगाने का काम किया था उन्होंने विवाद किया था और ट्रैक्टर जलाए थे। तीन महीने तक ये लोग उस काम को चालू नहीं कर पाए थे आज खुद उन्होंने इस काम को चलाने का प्रयास किया आखिर उन्होंने इस काम को छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार ने तो उस पहाड़ के ठेके दिए हैं जब कि उस पहाड़ की लूट का पैसा ये लोग खाया करते थे। उन लोगों ने जो उसी प्रकार से उसका विरोध करने का प्रयास किया तो हमने उन लोगों को समझा बुझा कर के सख्ती से उसको लागू करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, कहां तो 54 लाख आया करता था। चौधरी बंसी लाल सदन से चले गए हैं वे बैठे होते तो मैं उनको बताता कि निगान पहाड़ का ठेका 10 साल तक उनके भाई रघुवीर सिंह के नाम पर था। इस ठेके का चौधरी रघुवीर सिंह के नाम पर बेनामी सौदा था। यह ठेका धर्मवीर एंड कम्पनी के नाम से उन्होंने लिया हुआ था। ईश्वर वर गुप्त और रघुवीर सिंह पुत्र नौहक सिंह हासी रोड, भिवानी टंकेदार के जमानती श्री बंसी लाल के भाई रहे हैं। 1-4-1992 से 31-3-1995 तक, 8-4-1995 से 3-3-1998 तक और 18-4-1998 से 31-3-1999 तक चौधरी बंसी लाल के भाई उनके जमानती रहे हैं। इस ठेके से केवल 40 हजार रुपए सरकारी खजाने में जाते थे। एक अकेले पहाड़ के 40 हजार रुपए सरकारी खजाने में जाते थे। अब उस पहाड़ की ऑक्शन से 1.27 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस पहाड़ में जो ठेका दिया हुआ था उसमें क्या होता था, जो उस पहाड़ को तोड़ने वाले थे वे उस समय की सरकार को 24 रुपए प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी दिया करते थे। लेकिन जो 20 प्रतिशत सेल्ज टैक्स सरकार को देना होता था तो वे क्रैशर वाले कोरा-मेटिरियल बिना पर्ची के दे दिया करते थे। बंसी लाल जी जो पर्चियां यहां दिखाया करते थे अगर वे सदन में होते तो मैं उनको बताता कि क्रैशर वाले 20 प्रतिशत सेल्ज टैक्स बचाने के लिए उनको लिखित रूप में यह लिखकर नहीं देते थे कि उन्होंने इतना रा-मेटिरियल लिया है। क्रैशर वाले कच्चा पत्थर लेकर जो क्रैशर बनाते थे उस पर जो 12 प्रतिशत सेल्ज टैक्स लगता था वही सरकार के खजाने में जाया करता था। अध्यक्ष महोदय, हमने तो उनकी तरफ जो 60 लाख रुपए बकाया थे वे भी वसूल किए हैं। यह वसूली हमने 12 दिसम्बर से लेकर अब तक की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि 10 साल तक जिन्होंने उस पैसे को लूटा है, हम उनसे भी उस पैसे को वसूल करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रदेश को निरन्तर लूटते रहे थे उनके पास जहां पर पहले ठेका 52 से 54 लाख रुपए तक में जाया करता था अब वही ठेका 7 करोड़ रुपए से ज्यादा में नीलाम हुआ है। इसके बाद जो रॉयल्टी और सेल्ज टैक्स आएगा वह लगभग 18 करोड़ रुपए हर साल आएगा। अध्यक्ष महोदय, कितना ही पैसा हर साल इससे सरकार का बढ़ा है। ये लोग जो यहां पर चिन्ता करते थे कि ओम प्रकाश चौटाला घोषणा मुख्यमंत्री है, घोषणा ही करता है विकास के काम कहां से होंगे ? मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमने इस प्रकार से विकास के काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने मार्केट फीस को 3 रुपए से घटा कर 1 रुपया किया है लेकिन इसके बावजूद मार्केटिंग बोर्ड में काफी पैसा आया है। हमने व्यापारियों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी हैं परन्तु उसके बावजूद

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

भी हमारे पास काफी पैसा आया है। हमने दूसरे देशों में जाकर के अपने देश के उद्योगपतियों से बातचीत की है उनको हरियाणा में आने का निमन्त्रण दिया है, उनसे सम्पर्क स्थापित किया है और उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है जिस वजह से हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के उद्योग आए हैं जबकि इनकी सरकार के वक्त हरियाणा से उद्योग पलायन करने लग पड़े थे। हमारे वक्त में हरियाणा में नए उद्योग लगे हैं उनसे हमारे यहां पर उत्पादन बढ़ा है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है और किसानों का उत्पादन बढ़ा है इस वजह से आज यह परिणाम निकले हैं कि हमारा रैदेन्सू 37 प्रतिशत इन्क्रीज तक चला गया है। 37 प्रतिशत की इन्क्रीज की वजह से जो पैसा आया है वह जनता का पैसा है और हमने वह पैसा जनता पर ही खर्च करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार-बार कहते थे कि मेवला महाराजपुर में पैसा खर्च नहीं हुआ है। उनको ज्ञान नहीं है कि मेवला महाराजपुर में मैं पहले चरण में गया था और वहां के लोगों से पूछ करके वहां पर विकास का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, 5-6 विधान सभा क्षेत्र बाकी रह गए हैं दूसरे चरण में वहां पर भी जाएंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो भजन लाल और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के चुनाव क्षेत्रों में भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाले यहां पर नहीं है हम उन सबके चुनाव क्षेत्रों में भी गए हैं। हरियाणा प्रदेश में अब पता नहीं मतवाता किस खोच में वोट दे देते हैं और वे अपनी सोच बदल भी सकते हैं। समुनागर का प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण सबके सामने हैं। हमने अच्छे काम किए हैं इसलिए लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों के हितों के काम करते हैं। हमारी मंशा केवल एक ही है कि हम चौधरी देवी लाल जी के स्वप्नों को साकार करके हरियाणा प्रदेश को एक प्रगतिशील प्रदेश बना सकें और लोगों की मूलभूत जरूरियातें पूरी कर सकें। इसके लिए हमने हर क्षेत्र में काम किया है चाहे पशुधन को बढ़ावा देने की बात हो, हम यह मानकर चलते हैं कि आज खेती का जो मामला है उसकी वजह से किसान थोड़ा सा परेशान है क्योंकि गेहूँ और चावल का इतना उत्पादन बढ़ गया है कि देश के गोदाम भरे पड़े हैं, सटे पड़े हैं और सबको इसकी चिंता हो रही है। केन्द्र की सरकार भी चिंतित है कि इसको कैसे खपाया जाए ? इसीलिए हमने केन्द्र की सरकार को सुझाया है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे सुझाव को मानकर फूड फोर वर्क स्कیم के तहत वह गेहूँ हमें देना शुरू कर दिया है। अब इससे गावों के विकास के कार्यों को और ज्यादा तेजी मिलेगी, गांव का विकास बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने आवस्यकिकेक्षण की तरफ भी तवज्जो दी है और इसीलिए हमने गन्ने की मिल लगायी है। चौधरी बंसीलाल जी चले गए। वे कहते हैं कि सिरसा की गन्ना मिल गन्ने के अभाव की वजह से बंद हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, सिरसा की शुगर मिल में पहले साल में ही सबसे ज्यादा गन्ना क्रश हुआ है और दस परसेंट इसकी रिकवरी आयी है। पड़ली मर्तबा यह रिकवरी बढ़ी है। इनके वक्त में क्या हुआ है मेरे पास लिस्ट है अगर वे यहां पर होते तो मैं उनको बताता कि उनके वक्त में जो शुगर मिलें चली हैं उनमें पहले साल में किसी में एक लाख क्विंटल और किसी में 1.5 क्विंटल लाख गन्ना क्रश होता था लेकिन हमारी शुगर मिल ने पहले साल में 9 लाख क्विंटल से भी अधिक गन्ना क्रश किया है और दस परसेंट उसकी रिकवरी आयी है। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले चौधरी भजनलाल जी मेरी गैर हाजिरी में कुछ कह रहे थे। सम्पत सिंह ने उनको इसके लिए डांटा भी, वे कहते हैं कि चार साल से गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी नहीं पता है। वे पिछले सेशन में कभी तो कहते थे कि इंदिरा गांधी ने कहा था जबकि इंदिरा जी

तो स्वर्ण में थी उसके बाद वे कहने लगे कि राजीव गांधी ने कहा जबकि राजीव गांधी भी उस दौरान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान ही नहीं है कि कौन-कौन सी बात का यहां पर जिक्र किया जाए ? मैं सदन का समय खराब करना नहीं चाहता। अगर ये लोग हाउस में होते तो मैं उनको कुछ बताता। हम चाहते हैं कि किसान ज्यादा गन्ना पैदा करें क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो प्रकृति के प्रकोप को बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए गन्ना क्रश करने के लिए हमने दो शुगर मिलें लगायी हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर और अधिक गन्ना आएगा तो हम और शुगर मिल लगाएंगे। कृषि मंत्री शायद इसलिए ही देख रहे हैं कि हाथ के हाथ ही इस बारे में घोषणा कर दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि गन्ना किसान और ज्यादा पैदा करें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी शुगर मिलों ने किसानों के गन्ने के दाम साथ के साथ दे दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। हमने तो कांग्रेस की सरकार के वक्त का जो गन्ने का बकाया था, वह पैसे भी दिए हैं और किसान को और ज्यादा पैसा देने का काम किया है। हम डायवर्सिफिकेशन के हिसाब से जहां एक तरफ गन्ने की फसल को बढ़ावा देने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम अन्य फसलों की तरफ भी ध्यान देने जा रहे हैं। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील किसानों का एक डेलीगेशन इजरायल भेजा था ताकि वह डेलीगेशन फ्लोरीकल्चर को देख सके, सब्जी एवं फूलों की खेती को देख सके और वहां की डेयरी को देख सके। अध्यक्ष महोदय, हमने पशु विकास बोर्ड का भी गठन किया है। किसान के जो दुधारू पशु हैं हमने उनके लिए भी इनाम तय किए हैं। हमने 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक किसान को दूध पैदा करने के लिए इनाम देना तय किया है। हमने तय किया है कि 12 लीटर तक दूध पैदा करने वाले किसान को इतना, 12 से 15 लीटर तक दूध पैदा करने वाले किसान को इतना और 15 से 18 लीटर दूध पैदा करने वाले किसान को इतना इनाम दिया जाएगा। हमने किसान को आठ हजार रुपये तक दूध बढ़ाने के लिए दिए हैं ताकि वह प्रोत्साहित हो। इससे हमारी मुर्दा नरत्न भी कामचला रहेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बार हमारी केन्द्र की सरकार ने बाहर से आने वाले दूध पर एवं दूध के प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाया था। मैंने उसी वक्त प्रधानमंत्री जी से इसे बारे में जाकर कहा कि अगर आप बाहर से आने वाले दूध पर, दूध के प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर विदेशों का दूध और दूध से बनी हुई चीजें भारी मात्रा में यहां आएंगी और अगर ऐसा होगा तो इस प्रदेश का किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को मानकर बाहर से आने वाले दूध पर 60 परसेंट ड्यूटी लगा दी और उसका परिणाम यह निकला कि विदेशी दूध और दूध का बना सामान यहां पर नहीं आया। इसकी वजह से हमारे किसानों को बल मिला है। हम उनको इनाम देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान की गाय, भैंस और बैल के लिए लाजिमी बीमा स्कीम के तहत आधा पैसा सरकार देती है और आधा पैसा किसान देता है। इस तरह से हम किसान को पशुधन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो किसान के पशुओं की बीमारियों के लिए भी डिस्कर में एक सेंटर बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं इस पर सैकड़ों करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। हम चाहते हैं कि हरियाणा डेयरी के मामले में, दूध के मामले में डेनमार्क जैसे मुल्क को भी मात दे सके। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। हम फ्लोरीकल्चर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑयल सीड ज्यादा पैदा किया जाए। हम चाहते हैं कि पल्सेस ज्यादा पैदा की जाए उसके लिए किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएं किसानों को देने के पक्षधर हैं। हमने किसान को, व्यापारी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

को और उद्योगपति को हर मामले में सहूलियतें दी हैं। अभी शिक्षा के मामले को लेकर भी कुछ लोगों ने आपत्तियां की थी। हमने पहली जमात से अंग्रेजी की शिक्षा शुरू की और छठी जमात से कंप्यूटर की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है उस पर कुछ ने एतराज किया कि बिजली के बिना कंप्यूटर शिक्षा कैसे चलाएंगे ? मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए बाकायदागी से बिजली का पूरा प्रबंध किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम्प्यूटिशन में आगे बढ़ सकें और ग्रामीणोन्मुखी योजनायें बन सकें यह हमारा प्रयास है। हरियाणा प्रदेश के लोग विकास के कामों में आगे बढ़ सकें इसके लिए हम इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने गुडगांव में एक साइबर सिटी का फायनल कर दिया है और बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है आज हरियाणा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है और हम जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम पहले नंबर पर आएंगे (विघ्न) हमने खेलों को भी बढ़ावा दिया है चौधरी बंसी लाल के शासन के दौरान शराबबंदी के दौरान बच्चे दूसरी दिशा में मुड़ रहे थे जिनके बस्तों में किताबें होनी चाहिए थीं उनके बस्तों में किताबों के स्थान पर शराब के पाउचिज हुआ करते थे। वे गलत बातों की तरफ तवजो दे रहे थे। हमने उनके अटेंशन को डायवर्ट कर दिया है और खेलों के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं। हमने खिलाड़ियों को सर्विसेज में तीन परसेंट आरक्षण भी दिया है इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों को दी जाने वाली खुराक की राशि 15 रुपये से बढ़ाकर तीस रुपये दी है इसके अलावा बस्तों में मुफ्त साफर करने की अनुमति प्रदान की है। इस मौके पर मैं केन्द्र सरकार का भी आभार व्यक्त करूंगा कि चौधरी देवी लाल के नाम पर सोनीपत जिले में चौहान जोशी में चौधरी देवी लाल रीजनल सेंटर का काम शुरू कर दिया है। हमारा जो यूथ फेस्टीवल 12 से 16 तारीख तक था ऐसा फेस्टीवल इससे पहले भारतवर्ष में आज तक कहीं भी नहीं हो पाया था वहां उससे प्रभावित होकर केन्द्रीय खेल मंत्री जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। (इस समय मेज़ें थपथपाई गई) हम खेलों को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं हमने तो साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। हम चाहते हैं कि कल्चर को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा पुराना जो आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा है उसको मजबूत किया जा सके। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति करे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण प्रस्तुत किया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान जिन सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिए हैं मैं इस सदन को आश्चर्य करना चाहूंगा कि उनके रचनात्मक सुझाव जो ठीक होंगे, उनको निश्चित रूप से माना जाएगा। हम जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम बहुमुखी विकास के पक्षधर हैं जहां कहीं भी किसी भी सदस्य के क्षेत्र में विकास के कामों में दिक्कत आएगी वहां उनकी दिक्कतों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनका समाधान किया जाएगा। अब मैं ला एण्ड ऑर्डर के बारे में बताना चाहूंगा। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आज हरियाणा प्रदेश में ला एण्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा अच्छा है। (विघ्न) मुझे तो कांग्रेस के साधियों की ज्यादा चिंता है कभी ये किसी थाने में जाकर रपट दर्ज कराते हैं और कभी कहीं पर। (विघ्न) मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि चौधरी भजन लाल कहीं आत्महत्या न कर ले इसके लिए हम सिक्वोरिटी का प्रबन्ध करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि छूले महीने सरकार गिरा डूंगा। हम जब विपक्ष में हुआ करते थे तब भी ये ऐसी वैसी ही बातें किया करते थे तब भी ये हमारे किसी मंत्री को तोड़ नहीं पाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम जोड़ने वाले हैं तोड़ने वाले नहीं हैं। हम तोड़फोड़ की बात को बढ़ावा देने के पक्षधर नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम जनतांत्रिक

प्रणाली को बरकरार रखते हुए हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम चौधरी देवी लाल जी के स्वप्न को साकार करते हुए हरियाणा प्रदेश को पहले नंबर का प्रदेश बनाएंगे। अतः इसके लिए मैं आपसे और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण को ज्यों का त्यों मंजूर करें, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th March, 2002.”

The motion was carried.

वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Krishan Lal, Chairperson, Estimates Committee, will present the Report of the Committee on the Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

Chairperson, Estimates Committee (Shri Krishan Lal) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on the Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Now, the discussion and voting on the Supplementary Estimates will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands appearing on the order paper (No. 1 to 9, 11, 13 to 16 and 19 to 25) will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand No. on which they wish to raise the discussion.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,03,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 11,40,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

[Mr. Speaker]

course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 2- **General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 51,01,35,000/- for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 3- **Home.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 24,18,49,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 4- **Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,24,92,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 5- **Excise and Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 64,56,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 6- **Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,17,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 7- **Other Administrative Services.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 8- **Buildings and Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 29,29,81,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 9- **Education.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,74,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 11- **Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,01,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 13- **Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,19,50,000/- for revenue expenditure and Rs. 5,51,14,93,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 14- Food and Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 15- Irrigation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 300/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 16- Industries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,29,47,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 19- Fisheries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,65,47,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 20- Forest.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 82,98,91,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 21- Community Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,76,53,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 22- Cooperation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure and Rs. 4,90,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 23- Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 24- Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 85,23,77,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances By State Government.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, I put the various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is :—

(Mr. Speaker)

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,03,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 11,40,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 2- General Administration.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 51,01,35,000/- for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 3- Home.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 24,18,49,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 4- Revenue.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,24,92,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 5- Excise and Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 64,56,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 6- Finance.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,17,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 8- Buildings and Roads.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 29,29,81,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 9- Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,74,62,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the

course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 11- Urban Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,61,13,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,19,50,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 5,51,14,93,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 14- Food and Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 15- Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 300/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 16- Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,29,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 19- Fisheries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,65,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 20- Forest.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 82,98,91,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 21- Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,70,58,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 22- Cooperation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 4,90,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

[Mr. Speaker]
ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 23- Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 24- Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 85,23,77,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of Demand No. 25- Loans and Advances By State Government.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 13th March, 2002.

***13.43 hrs.** (The Sabha then *adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 13th March, 2002.)